विक्रम संवत् 2083 ▪ चैत्र/वैशाख मास (02) ▪ 01 अप्रैल 2026 ▪ मूल्यः 23 रु.

चरैवेति

आर. एन. आई. पंजीयन क्र.017261/69, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/297/2024-26, पृष्ठ संख्या - 44, प्रकाशन दिनांक प्रत्येक माह की 10 तारीख, पोस्टिंग प्रत्येक माह की 15 एवं 20 तारीख

जनता का हित सर्वोपरि

"नक्सल-मुक्त भारत"

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोबा तीर्थ में ''सम्राट संप्रति संग्रहालय'' का उद्घाटन किया।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

- भाजपा अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने राज्यसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।

- केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में परिर्वतन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पश्चिम एशिया की उभरती स्थिति के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ''कृषि और ग्रामीण परिवर्तन'' विषय पर वेविनार संवोधित किया।

- केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने पंजाव में वदलाव रैली को संवोधित किया।

अनुक्रमणिका

» **संपादकीय ▪ संजय गोविन्द खोचे** 04
▪ दूरदर्शिता ही काम आई
» **कवर स्टोरी ▪** 05
▪ जनता का हित सर्वोपरि

▪ नक्सल-मुक्त भारत 08
» "नक्सल-मुक्त भारत" अति महत्वपूर्ण सफलता - अमित शाह
▪ पश्चिम एशिया संघर्ष 14
» बातचीत और कूटनीति ही समाधान
▪ सेवा का कीर्तिमान 16
» मोदी जी ने सर्वाधिक समय तक सेवा का कीर्तिमान बनाया.......
▪ प्रशिक्षण महाअभियान 17
» देश और सीमाओं की रक्षा सर्वोपरि - डॉ. मोहन यादव
» भाजपा में विचारधारा स्थायी - हेमंत खण्डेलवाल
» भारत को आगे बढ़ाना लक्ष्य - डॉ. महेन्द्र सिंह
▪ कविता 20
» ऊँचाई
▪ मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक 21
» "टीम इंडिया" सबसे बड़ी ताकत
▪ जयपुर इन्टरेक्टिव सेशन 22
» अवसरों के केन्द्र मध्यप्रदेश से जुड़िए - डॉ. मोहन यादव
▪ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 23
» संघ ने राष्ट्रभक्ति का अलख जगाया - डॉ. मोहन यादव
▪ प्रतिक्रिया 24
» जनता को मिलेगी राहत - हेमंत खण्डेलवाल
▪ कृषक कल्याण वर्ष 25
» कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता - डॉ. मोहन यादव
▪ नेक्स्ट समिट 26
» लक्ष्य, मंजिल "विकसित भारत" - पीएम मोदी
▪ मन की बात 29
» 140 करोड़ भारतीयों की एकता पर भरोसा
» 'मन की बात' प्रेरणादायक है - नितिन नवीन
» समाज को सकारात्मक संदेश - डॉ. मोहन यादव
» आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली - हेमंत खण्डेलवाल
▪ बजट 2026-27 35
» बजट भविष्य के भारत की आधार शिला
▪ जयंती 38
» कट्टर देशभक्त डॉ. भीमराव अम्बेडकर
» शिवाजी ने कहा मेरा नहीं धर्म का राज्याभिषेक है
▪ विचार प्रवाह 41
» समाज और विचारधारा

05

08

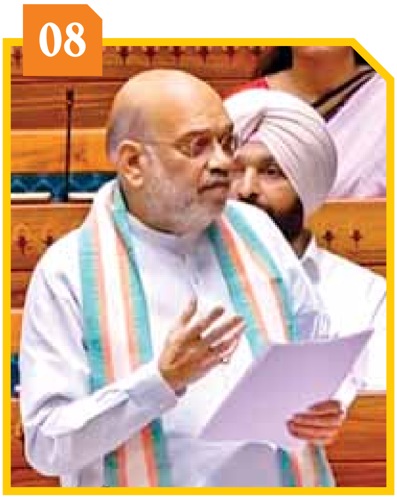

• मुख्य व्रत-त्यौहार

1. रेणुका चतुर्दशी, व्रत पूर्णिमा, दशलक्षण व्रत पूर्ण 2 स्ना. दा. पूर्णिमा, भ. हनुमान प्रा., रत्नत्रय व्रत पूर्ण 3. षोडषकारण व्रत पूर्ण 4. आसों दोज, 5. गणेश चतुर्थी व्रत 13. वरूथिनी एकादशी व्रत 15. प्रदोष व्रत, शिव चतुर्दशी व्रत 17. स्ना. दा. श्रा. सतुवाई अमावस्या 18. चन्द्रदर्शन 20. अक्षय तृतीया, विनायकी चतुर्थी व्रत 21. रोहिणी व्रत 23. गंगा सप्तमी, गंगोत्पत्ति 25. जानकी ज., सीता नवमी 27. मोहिनी एकादशी व्रत 29. प्रदोष व्रत 30. नृसिंह चतुर्दशी

• मुख्य जयंती-दिवस

1. हाटकेश्वर ज., गुरू हरकिशन पु. ति. 2. धरती पूजा 7. विश्व स्वास्थ्य दिवस 13. संत कंवरराम, वीरेन्द्रपुरी महा. ज., जलियाँवाला बाग दिवस 14. संत सेन जयंती, वैशाखी पर्व, भुंजिया एवं अग्नि निरोधक दिवस 22. संत सूरदास, रामानुजाचार्य जयंती, विश्व पृथ्वी दिवस 30. ग्राम जयंती

वर्ष-58, अंक : 02, भोपाल, अप्रैल 2026

हमारे प्रेरणास्रोत
पं. दीनदयाल उपाध्याय

ध्येय बोध

हमें सही व्यक्ति को वोट देना चाहिए न की उसके बटुए को, पार्टी को वोट दें किसी व्यक्ति को भी नहीं, किसी पार्टी को वोट न दें बल्कि उसके सिद्धांतों को वोट देना चाहिए।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

•

सम्पादक
मुद्रक एवं प्रकाशक
संजय गोविंद खोचे*

•

सहायक सम्पादक
पं. सलिल मालवीय

•

व्यवस्थापक
योगेन्द्रनाथ बरतरिया

•

पं. दीनदयाल विचार प्रकाशन म.प्र. के लिये
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय गोविंद खोचे द्वारा
पं. दीनदयाल परिसर, ई-2, अरेरा कालोनी,
भोपाल-462016 से प्रकाशित

एवं एम. पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेस-II, गौतमबुद्ध नगर,
नोएडा - 201 305 से मुद्रित.

•

संपादकीय पता
पं. दीनदयाल परिसर,
ई-2, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462016
e-mail:charevetibpl@gmail.com
web site:www.charaiveti.org

मूल्य- तेईस रुपये
*समाचार चयन के लिए पी.आर.बी.एक्ट के तहत जिम्मेदार

दूरदर्शिता ही काम आई

26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विश्व के तमाम देशों की सरकारों से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण विश्व के साथ सम्बन्धों में नया आयाम स्थापित किया। यह श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शिता ही थी कि विदेशी सम्बन्धों में प्रगाढ़ता आई। भारत और भारतीय, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं, जहाँ देश की जनता का भरोसा जीतने में मोदी जी सफल रहे वहीं विदेशियों का भी भरोसा मोदी जी पर अटूट बनता चला गया, मोदी जी ने ‘‘वसुधैव कुटुम्बकम’’ का पूर्णतः पालन किया, संकट के समय जहाँ भारतीयों का भरोसा मोदी जी पर स्थिर है, वहीं विदेशी सरकारों का भी भरोसा मोदी जी पर ही आकर स्थिर होता है। चाहे कोरोना की वैश्विक महामारी हो, भारत की स्वदेशी वैक्सिन भारतीयों के लिए, तथा सम्पूर्ण विश्व को वैक्सिन उपलब्ध कराने में कोई देरी नहीं की गई।

यूक्रेन युद्ध का संकट हो जहाँ भारतीयों को युद्ध रूकवा कर निकाला गया हो, तो विदेशियों को भी भारत के झण्डे के नीचे से निकलने में कोई हिचक नहीं हुई।

श्रीलंका में आर्थिक संकट के समय मोदी जी ही थे जिन्होंने श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट के दौर में सहायता पहुँचा कर गम्भीर संकट के दौर से बाहर निकाला। आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने घरेलू उड़ानों को अपना रक्षा कवच बनाया, फिर भी मोदी जी ने संयम का परिचय देते हुए आम नागरिकों के हितों की रक्षा करी। मोदी जी ने उन देशों से हाथ मिलाने में देरी नहीं करी जहाँ प्रधानमंत्री जी की यात्रा लम्बे अंतराल के बाद हुई। प्रधानमंत्री जी के इन प्रयासों का लाभ भारत व भारतीयों को मिलना ही था, इसी कारण सम्पूर्ण विश्व में भारतीयों का स्वागत किया जाता है। भारतीय पासपोर्ट सम्मान का प्रतीक बन चुका है।

प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज देश पर संकट आने से पहले ही देश संकट से निपटने का रास्ता बना चुका होता है। संकट आता है, और टल जाता है। मतलब संकटकाल निकल जाता है और देश फिर से पहले से तेज गति से प्रगति के पथ पर दौड़ने लगता है। अमेरिका-ईरान-इजराइल के युद्ध से पहले ही भारत ने क्रूड आयल के भण्डार भर रखे थे, पेट्रोल में इथेनाल की दो प्रतिशत की ब्लेंडिग करने वाला भारत अब बीस प्रतिशत की ब्लेंडिग कर रहा है।

ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम करने के तमाम प्रयास पहले ही सिद्ध हो चुके थे। निश्चित रूप से युद्ध के कारण संकटकाल था। पर भारत ऊर्जा आपूर्ति के लिए 27 देशों की जगह 41 देशों से एनर्जी आयात कर रहा था। रिन्यूएबल एनर्जी को पहले ही प्राथमिकता दे चुका था, यूरिया की आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयास पहले से जारी थे।

ईरान के साथ सम्बन्धों के कारण ही भारत के जहाज बेरोकटोक आ-जा रहे थे। खाद्यान्न भंडारण पर्याप्त था। युद्ध पर भारत के नजरिये को सभी पक्ष सराह रहे थे। विभिषिका को भारत ने लाभ का अवसर नहीं बनाया, बंगलादेश, श्रीलंका को डीजल आपूर्ति करने में देर नहीं की। बंगलादेश, श्रीलंका की जनता की ऊर्जा आवश्यकताओं को संकटकाल में मदद करने में भारत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया।

प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण युद्ध के संकट काल में 140 करोड़ नागरिकों का हमारा देश सामान्य समय की तरह ही अपने संकटकाल को आसानी से पार करने में सक्षम बना रहा। वैश्विक स्थितियां और परिस्थितियां तो बनती बिगड़ती रहेंगी, सफलता प्रधानमंत्री जी की इस बात में है कि ऐसी असामान्य परिस्थितियों में भी नागरिकों को कोई कष्ट न हो इस मापदंड में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी बहुत ज्यादा सफल हुए हैं। हर संकटकाल का सामना प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सामने से आकर किया और भारत के नागरिकों को संकट काल में पूर्ण सुरक्षा देने में सदैव कामयाब सिद्ध हुए।

नक्सलवाद भारत की राजनीति में कैंसर की तरह दर्द दे रहा था, और पूर्व के सरकारी संरक्षण में भोले-भाले आदिवासियों को अपने जाल में फंसा कर निगल रहा था, हजारों नागरिकों की बलि ले चुका था, हजारों महिलाओं को विधवा कर चुका था, हजारों बच्चों को अनाथ बना कर दर्द भरा जीवन दे चुका था। इस भीषण समस्या ने समानांतर सरकार चलाना शुरू कर दिया था। नक्सलवाद, सरकार व विकास को प्रभावित क्षेत्रों में घुसने नहीं देता था। गरीबों का हमदर्द बनकर उन्हें दर्द भरी जिन्दगी में धकेलने का कार्य कर रहा था, इस दर्द का आभास सिर्फ मोदी जी को हुआ, मोदी जी ने इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। प्रयासों में एकाग्रता व सघनता लाई गयी और 30 मार्च 2026 को देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में देश को नक्सलवाद से मुक्त होने की घोषणा की। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं और सफलताओं में नक्सलवाद से मुक्ति बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। आज मोदी जी के निर्णय और अथक प्रयासों से नक्सलवाद अब इतिहास के पन्नों में दब कर खत्म हो गया। मोदी सरकार की यह सफलता बहुत प्रशंसनीय है।

आंतरिक व वैश्विक परिस्थितियों में देश को नेतृत्व केवल और केवल भाजपा ही दे सकती है। भीषण संकटकाल में देश को उबारना केवल भाजपा ही जानती है। भाजपा की असली ताकत उसके प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। भाजपा प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर भविष्य को नेतृत्व प्रदान करती है। प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का नेतृत्व ही देश को चारों दिशाओं में सुरक्षित व भविष्य उन्नत बनाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश मे प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। इस प्रशिक्षण अभियान से भाजपा और बड़ी ताकत बन कर उभरेगी और प्रदेश-देश को समर्पित,योग्य व प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की प्राप्ति होगी। प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही राजनीति को नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। ■

(संजय गोविन्द खोचे)
सम्पादक

जनता का हित सर्वोपरि

शांति और संवाद की हमारी एकजुट आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे

सरकार हर चुनौती का समाधान करेगी।

(पश्चिम एशिया संघर्ष पर राज्यसभा में पीएम मोदी)

- एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में निवास करते हैं और वहाँ कार्यरत हैं, उनके जीवन और जीविका की सुरक्षा भारत के लिए एक अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है।
- पश्चिम एशिया में छिड़े इस युद्ध को तीन सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है और इस संघर्ष ने संपूर्ण विश्व के समक्ष एक गंभीर ऊर्जा संकट उत्पन्न कर दिया है।
- वाणिज्यिक जहाजों पर हमले और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में व्यवधान पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
- भारत ने नागरिकों, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ऊर्जा और परिवहन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों की निंदा की है।
- युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक, पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो दौर की टेलीफोन वार्ता की है।
- सभी खाड़ी देशों के साथ निरंतर संपर्क में हैं, साथ ही, हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी लगातार संवाद बनाए हुए है।
- हमारा लक्ष्य संवाद और कूटनीति के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति बहाल करना है।

होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रूमेंबर्स हैं। यह भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।

चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील घड़ी में, यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत की संसद के उच्च सदन से संपूर्ण विश्व के लिए शांति और संवाद का साझा एवं एकजुट स्वर गूँजे।

अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और सरकार तेजी से बदलती परिस्थितियों पर पैनी नजर रख रही है।

- संबंधित पक्षों के साथ क्षेत्रीय तनाव को कम करने और होर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही पुनः बहाल करने पर भी चर्चा की है।
- युद्ध के इस कठिन वातावरण में भी भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत कूटनीतिक माध्यमों से निरंतर प्रयास कर रहा है।
- युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज स्ट्रेट मे जहाजों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से रास्ता बनाने का प्रयास किया है।
- निरंतर प्रयास है कि जहाँ से भी संभव हो, भारत को तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और देश ऐसे प्रत्येक प्रयास के सकारात्मक परिणामों का साक्षी बन रहा है।
- पिछले कुछ दिनों में विश्व के कई देशों से कच्चे तेल और एलपीजी लेकर जहाज भारत पहुँचे हैं और इस दिशा में प्रयास आने वाले दिनों में भी निरंतर जारी रहेंगे।
- सरकार वर्तमान परिस्थितियों के अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक प्रभावों के समाधान हेतु एक सुनियोजित रणनीति के साथ काम कर रही है।
- सरकार ने उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ कर ली हैं।

- **सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि किसी भी संकट का बोझ किसानों पर न पड़े।**
- **किसानों कि हर चुनौती के समाधान के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है।**

पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है। गल्फ देशों में करीब एक करोड़ भारतीय रहते हैं, वहां काम करते हैं। उनके जीवन और आजीविका की सुरक्षा भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। होर्मुज स्ट्रेट में दुनिया के अनेक जहाज फंसे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रूमेंबर्स हैं। यह भी भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थिति में आवश्यक है कि भारत की संसद के उच्च सदन से शांति और संवाद की एकजुट आवाज पूरे विश्व में जाए।

युद्ध की शुरुआत के बाद से पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दो राउंड फोन पर बात की है। गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ संपर्क में हैं। लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। डिएस्केलेशन और होर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का सतत प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है।

संकट की स्थिति में देश-विदेश में भारतीयों की सुरक्षा बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से 3 लाख 75 हजार से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही 1000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सभी देशों ने वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है।

होर्मुज स्ट्रेट विश्व व्यापार के सबसे बड़े रूट्स में से एक है। विशेष तौर पर कच्चे तेल, गैस और फर्टिलाइजर से जुड़ा परिवहन इस क्षेत्र से बहुत बड़ी मात्रा में होता है। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट मे जहाजों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने संवाद से, कूटनीति के माध्यम से रास्ते बनाने का प्रयास किया है। प्रयास यह है कि जहां से भी संभव हो, वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। ऐसी हर कोशिश के नतीजे भी देश देख रहा है। दुनिया के अनेक देशों से कच्चा तेल और एलपीजी से भरे जहाज भारत आए हैं। इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे।

भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेसिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उनको और गति दे रहा है।

कोई भी संकट हो, वह हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डायवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है।

पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी, ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारों को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक तक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही, बीते दशक में भारत की रिफायनिंग कैपेसिटी भी अच्छी-खासी बढ़ाई गई है।

भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं।

सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता ना रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम

हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही, एलजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों, यही एक मात्र विकल्प है। जैसे भारत का 90 प्रतिशत से अधिक तेल विदेशी जहाजों पर होता है, यह स्थिति किसी भी वैश्विक संकट में भारत की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। इसलिए सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू किया है। भारत आज शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, मेंटेनेंस एंड ओवरहालिंग, ऐसी हर सुविधा के निर्माण पर तेज गति से काम कर रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को भी अधिक रेसिलियंट बना रहा है। बीते दशक में किए गए प्रयासों से भारत आज अपनी जरूरत के अधिकांश हथियार भारत में ही बना रहा है। एक समय था, जब भारत अपने जीवन रक्षक दवाओं के कच्चे माल यानी API के लिए भी दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भर था। बीते वर्षों में देश ने भारत में ही API इकोसिस्टम बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इसी प्रकार रेयर अर्थ मिनिरल्स में विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है। अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है, उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा। भारत में इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहे हैं। हमारे इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल-पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है, यह ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट - एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है और यह ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है। जैसे कोरोना के समय में अलग-अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपोर्ट्स और ऑफिसर्स के empowered groups बने थे, वैसे ही 7 नए empowered groups का भी गठन किया गया है। यह ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल-डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई, ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्यवाही करने का काम करेंगे। इस साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे।

सरकार प्रयास कर रही है कि आने वाले बुवाई के सीजन में किसानों को पर्याप्त खाद मिलती रहे। सरकार ने खाद की पर्याप्त सप्लाई के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। सरकार का निरंतर प्रयास है कि किसानों पर किसी भी संकट का बोझ ना पड़े।

आने वाले समय में यह संकट हमारे देश की बड़ी परीक्षा लेने वाला है और इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। संकट के समय गरीबों पर, श्रमिकों पर, प्रवासी साथियों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ समय पर मिलता रहे, यह सुनिश्चित करना होगा। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें, तो इससे काफी सुविधा होगी।

ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, यह सुनिश्चित करना हर राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भारत की तेज ग्रोथ बनाए रखना, हम सभी का दायित्व है। हमें इसके लिए हर जरूरी कदम, हर जरूरी रिफॉर्म्स तेजी से करते रहने होंगे। यह राज्य सरकारों के पास बहुत बड़ा अवसर भी है। यह टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। कोरोना के महासंकट में केंद्र और राज्यों ने टीम इंडिया बनकर कोविड मैनेजमेंट का एक बेहतरीन मॉडल सामने रखा था। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें होने के बावजूद टेस्टिंग, वैक्सीनेशन से लेकर जरूरी चीजों की आपूर्ति टीम इंडिया के प्रयासों से ही निश्चित हो पाई थी। हमें उसी भावना के साथ आगे भी काम करना है। सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के प्रयासों से देश इस गंभीर वैश्विक संकट का प्रभावी रूप से सामना कर पाएगा।

यह संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किया जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है।

हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है। लेकिन सरकार सतर्क है, तत्पर है और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। ■

“नक्सल-मुक्त भारत” अति महत्वपूर्ण सफलता - अमित शाह

- **गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, नक्सलवाद के कारण गरीबी फैली।**
- **कम्युनिस्ट पार्टी अन्याय का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी संसदीय प्रणाली का विरोध करने के लिए बनी।**
- **जिस कम्युनिस्ट पार्टी की नींव ही दूसरे देश की विचारधारा से प्रेरित हो, वो भारत का भला कैसे करेगी?**
- **माओवादियों ने रेड कॉरिडोर, भेदभाव का विरोध करने के लिए नहीं बल्कि सरकार की पहुँच कम होने के कारण चुना था।**
- **वामपंथी विचारधारा के समर्थकों ने भगवान बिरसा मुंडा, शहीद भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस को नहीं बल्कि “MAO” को अपना आदर्श माना।**
- **नक्सल मुक्त भारत, मोदी सरकार की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सफलता**
- **वामपंथी उग्रवादियों ने दशकों तक जहाँ विकास नहीं पहुंचने दिया, वहां मोदी सरकार में घर-घर विकास पहुंच रही है।**
- **मोदी सरकार डरने वाली नहीं बल्कि सबके साथ न्याय करने वाली सरकार है।**
- **सत्ता के समर्थन के बिना देश के बीचों-बीच, तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक, रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं था।**
- **वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी है इसलिए सारे वामपंथी अलग-अलग थ्योरी रच-रच कर अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं।**

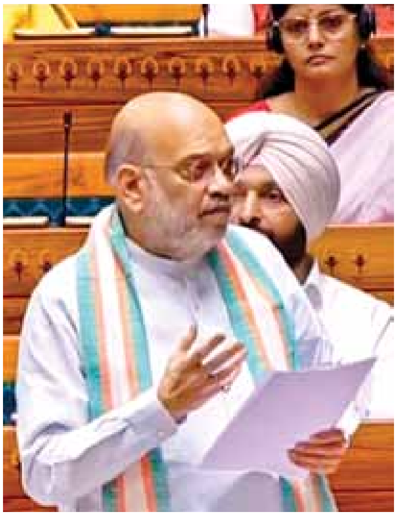

नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी नहीं, बल्कि वामपंथी विचारधारा है, जिसे 1969 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए तत्कालीन सत्तारूढ़ दल की नेता ने इसे स्वीकार कर लिया था।

लाल आतंक की परछाई थी, इसलिए बस्तर विकास से पिछड़ गया था, लाल आतंक की परछाई हट गई, अब बस्तर विकसित हो रहा है।

नक्सलियों के कारण हुए नरसंहार में नक्सलियों के समर्थक भी उतने ही भागीदार हैं जितना हिंसा करने वाले हैं।

- **नक्सलियों ने गांवों में स्कूल, दवाखाने और बैंक जला दिए, फिर लोगों को बरगला कर बोलते थे विकास नहीं पहुंचा।**

वामपंथी उग्रवादियों और उनके समर्थकों ने भोले भाले आदिवासियों के सामने एक गलत प्रकार का नेरेटिव रखा गया था कि वे उनके अधिकारों और उन्हे न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है और वहां हर गांव में स्कूल बनाने और राशन की दुकान खोलने की मुहिम शुरू हो चुकी है। नक्सलवाद की वकालत करने वाले बताएं कि 1970 से अब तक यह सब क्यों नहीं हुआ। 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद पूरे देश के हर गरीब को घर, गैस, पीने का पानी, 5 लाख तक का बीमा, 5 किलो मुफ्त अनाज मिला, लेकिन बस्तर वाले छूट गए क्योंकि सत्य को झुठलाया गया और लाल आतंक की परछाई के कारण वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक इसीलिए नहीं था कि वहां विकास नहीं था, बल्कि लाल आतंक के कारण वहां विकास नहीं हुआ था, लेकिन आज लाल आतंक की परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है।

यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है और जो भी हथियार उठाएगा उसे हिसाब चुकता करना पड़ेगा। सरकार संवेदनशील है और सभी समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना चाहती है। सरकार ने योजनाएं बनाई हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करने देंगे क्योंकि वामपंथी उग्रवादी और उनके समर्थकों की आइडियोलॉजी यानी उनका अवैध शासन वहां चलता रहे। आजादी के बाद 75 साल में से 60 साल तक देश में मुख्य विपक्षी पार्टी का शासन रहा तब भी आदिवासी विकास से महरूम कैसे रहे। विकास तो अब नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी को अपने अंदर झांककर देखना चाहिए कि दोषी कौन है।

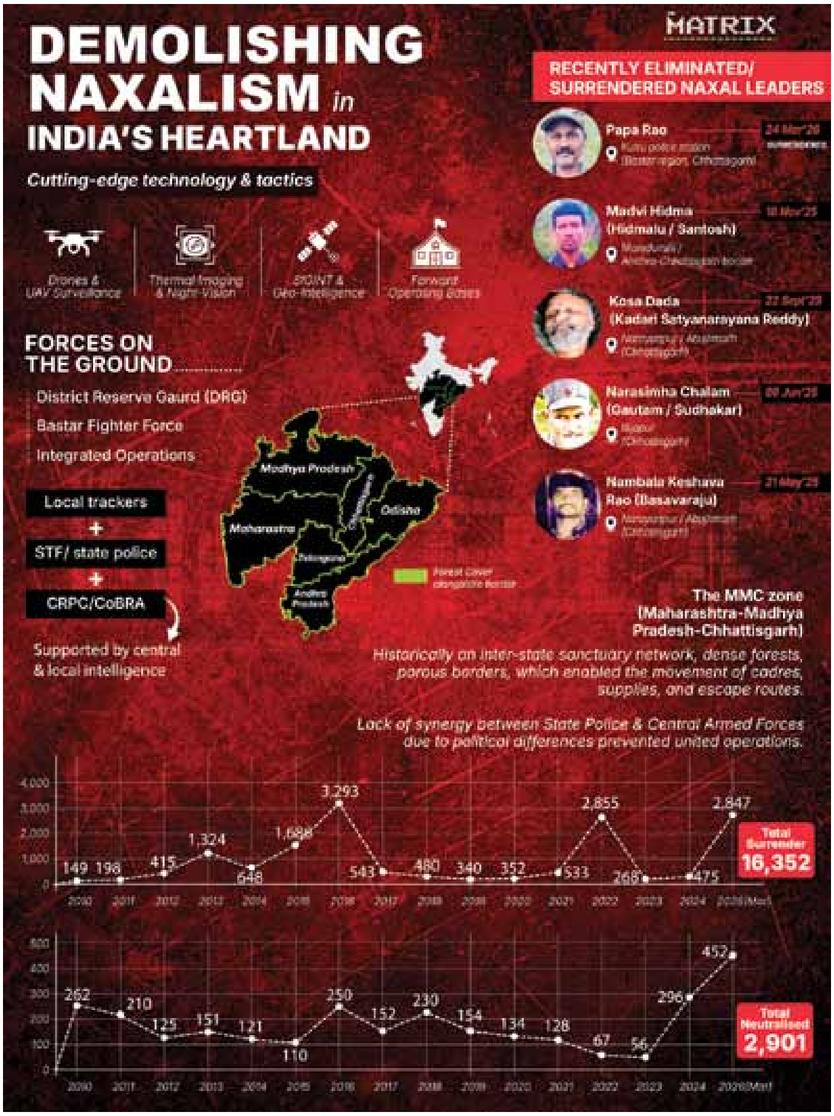

छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश के 3 जिलों सहित 12 राज्यों में पूरा रेड कॉरिडोर बनाकर रखा था। इन क्षेत्रों में 12 करोड़ लोग सालों तक गरीबी में जीते रहे और 20,000 युवा मारे गए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। नक्सलवाद का मूल कारण विकास की मांग नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी है। नक्सलवाद का मूल कारण विकास की कमी नहीं बल्कि वामपंथी विचारधारा है, जिसे 1969 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए तत्कालीन सत्तारूढ़ दल की नेता ने स्वीकार कर लिया था।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के सामने स्वीकार किया था कि कश्मीर और नॉर्थईस्ट की तुलना में देश की आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी समस्या हथियारबंद माओवादी हैं। 2014 में परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन में कई वर्षों पुरानी समस्याओं का निराकरण हुआ, धारा 370 और 35A हट गई, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन चुका है, GST आज वास्तविकता बन चुका है, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) बन चुका है, विधायी मंडलों में मातृशक्ति को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। आजादी के वक्त से इस देश की जनता, जो कई सारे बड़े काम चाहती थी, वे सभी काम नरेन्द्र मोदी जी के शासन के 12 साल में हुए और अब नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना भी नरेन्द्र मोदी जी के शासन के अंदर ही होगी। पिछले 12 साल देश के लिए बहुत शुभ साबित हुए हैं। देश को गरीबी से मुक्ति दिलाने, युवाओं के लिए नई शिक्षा पद्धति लाने, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने, देश के मूलों से न जुड़ी नीतियों को दरकिनार करने के लिए गत 12 साल में बहुत कुछ हुआ है। अगर सबसे अधिक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले को देखा जाए तो निसंकोच नक्सल मुक्त भारत सबसे ऊपर होगा।

इस विचारधारा का विकास और विकास की मांग से भी कोई लेना देना नहीं है।

यह कौन सी विचारधारा है?
क्या है माओवादी विचारधारा?
इसका ध्रुव वाक्य क्या है?

इनका ध्रुव वाक्य है कि- सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ये विकास के लिए नहीं बल्कि अपनी आइडियोलॉजी के अस्तित्व, उसकी विजय और आइडियोलॉजी को भोले-भाले आदिवासियों में फैलाकर कर सत्ता हासिल करने के लिए है। इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। कुछ लोगों ने इनकी तुलना भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से कर दी। शहीद भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा, जो अंग्रेजों के सामने लड़े, उनकी तुलना आप संविधान तोड़कर हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों लोगों के साथ कर रहे हैं? यह विचारधारा कहती है कि दीर्घकालीन युद्ध ही उनकी विचारधारा को फैला सकता है। उनको अपने लोगों का खून बहाने से भी कोई परहेज नहीं है। इस विचारधारा के समर्थकों ने भगवान बिरसा मुंडा, शहीद भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस को नहीं बल्कि माओं को अपना आदर्श माना है।

सच्चाई यह है कि इन्होंने पूरे रेड कॉरिडोर को इसीलिए चुना था क्योंकि वहां राज्य की पहुंच कम थी। भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर उनके हाथों में हथियार पकड़ा दिए गए। जो आदिवासी 15 अगस्त 1947 से पहले भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती, मुर्मू बंधुओं को हीरो मानकर चलता था, वह आदिवासी 1970 आते-आते माओ को अपना हीरो कैसे मानने लगा? विकास और अन्याय के कारण नहीं बल्कि कठिन भूगोल और राज्य की अनुपस्थिति के कारण अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने इस क्षेत्र को चुना और भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाना शुरू किया। वामपंथी उग्रवादियों

ने सालों तक उस क्षेत्र में विकास को पहुंचने नहीं दिया, लेकिन अब नरेन्द्र मोदी जी के शासन में वहां घर-घर विकास पहुंच रहा है।

गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में वर्षों तक गरीबी रही। नक्सलवाद की जड़ें गरीबी और विकास से नहीं जुड़ी बल्कि वैचारिक हैं।

नक्सलबाड़ी में साक्षरता का दर 32 प्रतिशत, बस्तर में 23 प्रतिशत, सहरसा, बिहार में 33 प्रतिशत और बलिया, उत्तर प्रदेश में 31 प्रतिशत था। इसी प्रकार, नक्सलबाड़ी में प्रति व्यक्ति आय 500, बस्तर में 190, सहरसा में 299 और बलिया में 374 थी। चारों क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय भी एक समान थी, लेकिन नक्सलबाड़ी और बस्तर में वामपंथी उग्रवाद पनपा और सहरसा और बलिया में नहीं। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सहरसा और बलिया का भूगोल उनके अनुकूल नहीं था, वहां घने जंगल, नदी नाले, छुपने की पहाड़ियां नहीं थी, हथियार लेकर अपनी मूवमेंट करने, आदिवासियों को दबाने और उनको जबरदस्ती अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की अनुकूलता नहीं थी। अगर विकास ही पैमाना होता, अगर प्रति व्यक्ति आय ही पैमाना होता, तो देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां 1970 में विकास नहीं पहुंचा था, लेकिन वहाँ नक्सलवाद क्यों नहीं फैला?

ये डरने वाली नहीं बल्कि सबके साथ न्याय करने वाली सरकार है। 1970 के दशक में नक्सलवाद की शुरुआत नक्सलबाड़ी और बंगाल से हुई। 1971 के एक ही वर्ष में वहां 3620 हिंसा की घटनाएं हुई थीं,1980 का दशक आते-आते पीपल्स वॉर ग्रुप बन गया और फिर यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा राज्यों में फैला। 1990 के दशक में वामपंथी विचारधारा सिकुड़ती गई और यहां पर भी उग्रवादी गुटों और वामपंथी पार्टियों में विलय शुरू हुआ। 2004 में दो प्रमुख गुट मिल गए और सीपीआई माओवादी का गठन किया। 1970 से 2004 के कालखंड में चार साल छोड़कर पूरा समय मुख्य विपक्षी पार्टी का शासन रहा है।

यही समय है जब नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन 12 राज्यों, देश के 17 प्रतिशत भूभाग और 10 प्रतिशत से ज्यादा आबादी में पहुंच गया। सत्ता के समर्थन के बगैर देश के बीचों-बीच, तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक, रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं था। जो हथियार पकड़े गए हैं, उसमें से 92 प्रतिशत हथियार पुलिस से लूटे हुए थे। थाने लूट लिए गए, गोलियां लूट ली गई और उनका उपयोग निर्दोष जवानों, बच्चों, कृषकों को मारने के लिए किया गया। वामपंथी विचारधारा ने इसे एक भ्रांति की तरह प्रोपेगेंडा के माध्यम से अपनी विचारधारा को टिकाने के लिए फैलाया कि अन्याय से बचने के लिए हथियार हाथ में उठाए।

लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि किसी भी समस्या का समाधान बहस से निकल सकता है, हथियारों से नहीं। नक्सलियों ने इस देश में वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया, स्टेट का वैक्यूम, सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान से श्रद्धा खत्म कर संविधान का वैक्यूम और पुलिस थानों को जलाकर सिक्योरिटी वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया है। माओवादी और नक्सली हिंसा करने वालों के दिन अब लद गए हैं और मोदी सरकार में ये लंबे समय नहीं चलेगा।

माओवादी उग्रवादियों को अन्याय के खिलाफ हथियारों की लड़ाई लड़ने वालों की तरह मानने की गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी है इसलिए सारे वामपंथी अलग-अलग थ्योरी रच-रच कर अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हैं। इनका एकमात्र एजेंडा है, देश में वैक्यूम खड़ा करना है। स्टेट, गवर्नेंस, संविधान और सिक्योरिटी का वैक्यूम खड़ा कर रक्तपात करना ही उनका उद्देश्य है जो अब सफल नहीं होगा। नक्सलियों ने कई सारे भोले-भाले ग्रामीणों को एनिमी इन्फॉर्मर बताकर फांसी पर चढ़ा दिया। इन्होंने जनता अदालत के नाम से एक दिखावा किया जहां न कोई वकील है, न जज है, वे स्वयं बैठे हैं, स्वयं फैसले करते हैं और फांसी देते हैं।

नक्सलियों ने ना जनता ना सरकार के नाम से एक भ्रांति खड़ी की और विकास योजनाओं को रोकने का काम किया। इन्हें संविधान और न्याय व्यवस्था को निशाना बनाकर संविधान का वैक्यूम खड़ा करना था। जो लोग अब कह रहे हैं बातचीत करो, उनको पता होना चाहिए कि मैं 50 बार सार्वजनिक मंचों पर बस्तर में जाकर कह चुका हूं कि हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। सरकार की पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, लेकिन जो गोली चलाता है, उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है।

जैसे ही रूस में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई। जब रूस में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई की स्थापना हुई। इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? रूस की सरकार ने स्पॉन्सर कर दुनियाभर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की। अब जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से की गई है, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेगी? इन्होंने तो अंग्रेजों का भी समर्थन किया था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बनी, ये भी समझने की बात है कि सीपीआईएम क्यों बना? यह भी समझना पड़ेगा कि जब सीपीआई थी, तो फिर सीपीआईएम क्यों बनी? 1964 में सोवियत रूस और चीन के बीच झगड़ा हुआ तो दोनों साम्यवादी राष्ट्र के अंदर अलग-अलग विचारधारा की साम्यवादी सरकारें आई। जैसे ही अलग-अलग विचारधारा की सरकारें आई, तो यहां पर चीन की एक समर्थित पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट बना दी। इसके बाद 1969 में संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य विकास का वैक्यूम बनाना या अधिकारों की रक्षा नहीं था बल्कि उसके संविधान में उद्देश्य था संसदीय राजनीति का विरोध कर सशस्त्र क्रांति करना।

इन्होंने सशस्त्र क्रांति और संसदीय राजनीति का विरोध करने के दो उद्देश्यों के साथ सीपीआई मार्क्सिस्ट बनाई और यही आज के माओइस्ट हैं। उसके बाद 1975 में जैसे ही कांग्रेस का समर्थन मिला, एमसीसी माओइस्ट बनी और बिहार झारखंड केंद्रीय पार्टी बनी। फिर पीडब्ल्यूजी 1980 में बना। वह आंध्र केंद्रित बना। 1982 में दलित किसान केंद्रीय सशस्त्र संघर्ष सीपीआई एमएल पार्टी यूनिटी बिहार में बनी। दलित किसान केंद्रीय संघर्ष उनका उद्देश्य था। 1998 में पीपल्स वॉर ग्रुप बना और उसमें माओवादियों का एकत्रीकरण हुआ। इतना सब करने के बाद भी वह सफल नहीं हुए और 2000 में पीएलजीए बना, गुरिल्ला फोर्स बनाई और 2004 में ये पीडब्ल्यूजी एमसीसी का विलय हो गया। 2014 में मोदी जी आए और 2026 में सब की समाप्ति हो गई। ये 1925 से लेकर 2026 तक 101 साल का उनका इतिहास है। इसे अन्याय के खिलाफ संघर्ष का स्वरूप मानकर महिमामंडित मत करो। ये लोग वोट की जगह बुलेट से शासन प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग चर्चा से मानते नहीं है, वहां बल प्रयोग कर उनके अत्याचार से निर्दोष नागरिकों को बचाना पड़ता है। ये हमारी पार्टी की सरकार है और हर नागरिक की सुरक्षा नरेन्द्र मोदी जी ने सुनिश्चित

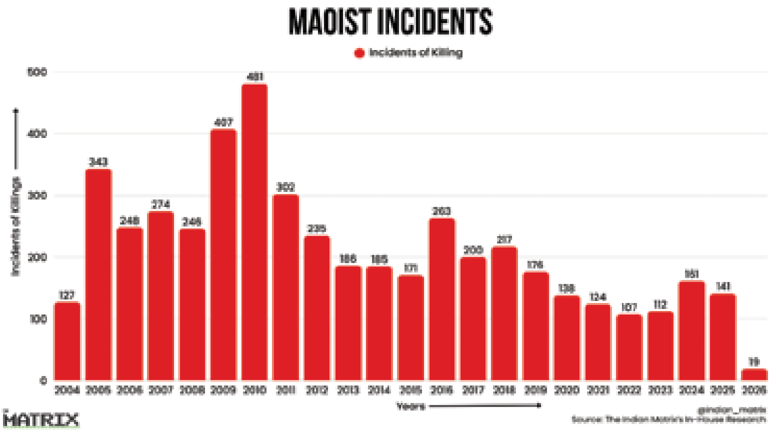

Source: The Indian Matrix's In-House Research

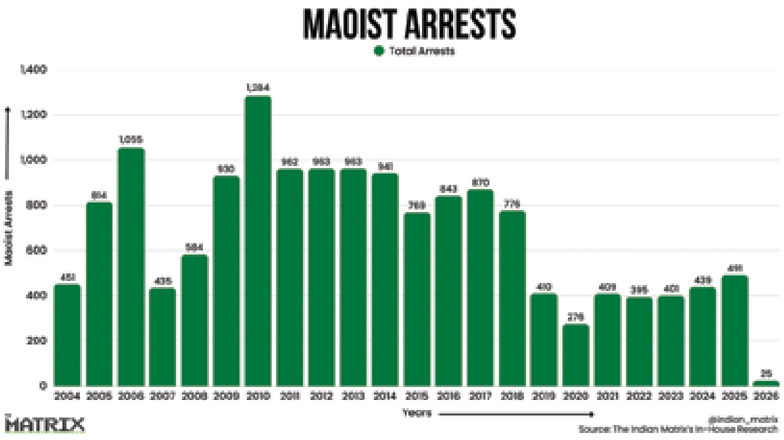

Source: The Indian Matrix's In-House Research

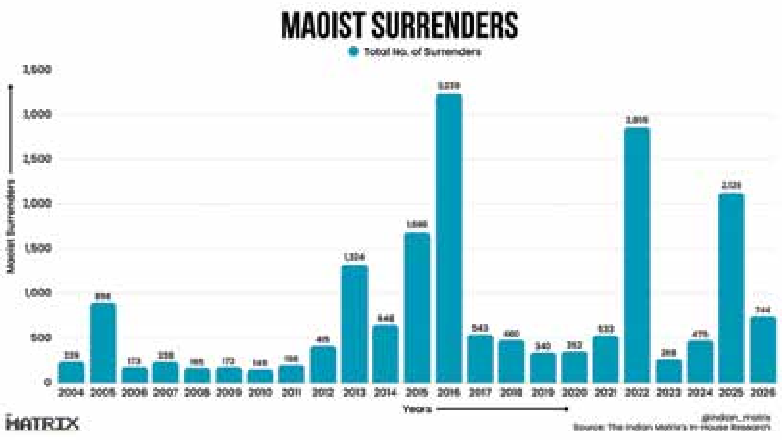

Source: The Indian Matrix's In-House Research

की है। जो भी नागरिकों के साथ अन्याय करेगा, समझा तो ठीक है वरना ये फोर्स इसी के लिए बनाई गई है। इसका उपयोग भी होगा, परिणाम भी आएगा और आज आ भी गया है।

अर्बन नक्सली कहते हैं कि हथियार उठाकर घूमने वाले माओवादियों के साथ चर्चा करो क्योंकि वो अन्याय के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें मारना नहीं चाहिए और इनके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए। एक भी बुद्धिजीवी दिव्यांग बनने वाले किसान, 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों, उनकी विधवाओं के लिए नहीं है, इनके अनाथ बच्चों के लिए नहीं लिखता। इनकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मानवता के दोहरे चरित्र को स्वीकार नहीं कर सकते, यह मानवतावादी नहीं हैं, बल्कि नक्सलियों के समर्थक हैं। ये लोग गरीबों के हाथ में हथियार देकर अपनी विचारधारा को फैलाना चाहते हैं, मगर उनके भी दिन लद गए हैं।

सलवा जुडूम की शुरुआत 2005 में सरकार समर्थित जनआंदोलन के रूप में हुई। आदिवासी युवाओं को एसपीओ बनाया गया और उनको आतंक फैलाने वालों के सामने लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई। सलवा जुडूम की शुरुआत श्रीमान कर्मा ने की थी जिन्हें नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था। 5 जुलाई 2011 को सर्वोच्च अदालत में नंदिनी सुंदर और अन्य लोगों ने एक विवाद दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नेतृत्व में तय किया कि नक्सलियों के खिलाफ राज्य की ये लड़ाई गैरकानूनी है और तुरंत ही इनको हथियार वापस देने का ऑर्डर कर दिया। इसका परिणाम हुआ उनके हथियार वापस दिए गए और इन्होंने चुन-चुन कर सलवा जुडूम से जुड़े हुए लोगों को मार दिया और वही सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने। जो देश की कानून और व्यवस्था को मानते हैं, वो सुदर्शन रेड्डी को कभी अपना प्रत्याशी नहीं बनाते। अगर कोई व्यक्ति जज बनकर अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी का उपयोग कर, संवैधानिक कपड़े पहनकर, अपनी आइडियोलॉजी को ऑर्डर में कन्वर्ट कर, हजारों बेगुनाह आदिवासियों की जान जाए ऐसा फैसला देता है, तो इस जजमेंट की घोर निंदा करते हैं। आइडियोलॉजी जनता के कल्याण से ऊपर नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में 17,589 किलोमीटर सड़कें बनाने की मंजूरी दी है, जिसमें 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। विकास इसीलिए हो रहा है कि धीरे-धीरे नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। लगभग 5,000 मोबाइल टावर, ₹6,000 करोड़ के खर्चे से हम लगा चुके हैं। दो अन्य योजनाओं में और 8,000 4G टावर बनाने का फैसला नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। 1804 बैंक शाखाएं 12 साल में खुली हैं, 1321 एटीएम खुले हैं, 37,850 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस बनाए गए और 6025 डाकघर खुले। यह सब सिर्फ 12 साल में हुआ है। हमने माओवादियों के साथ चर्चा नहीं की, उन्हें समाप्त किया और विकास को

आगे बढ़ाया। 259 एकलव्य आदर्श विद्यालय बनाए, इसके साथ-साथ 46 आईटीआई, 49 स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए, 16 कौशल विकास केंद्र बनाए और लगभग इस सबके लिए 800 करोड़ रुपए का खर्च 12 साल में हमने किया है। सिविक प्रोग्राम में 212 करोड़ के कार्य किए जो स्वास्थ्य शिविर और दवाओं से जुड़े हुए हैं और जनजाति युवा एक्सचेंज के कार्यक्रम भी हमने बनाए। सिक्योरिटी के लिए राज्यों की सहायता के लिए एसआरई लेकर आए जिसमें 10 साल में 3000 करोड़ दिया। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर आए और इसमें 5000 करोड़ दिया। ये सब 1970 से अब तक क्यों नहीं हुआ था? पिछली सरकारें करने जाती थीं तो वो धमाके कर मार देते थे। हमने धमाके करने वालों को समाप्त किया, तो अब विकास हो रहा है।

2014 के बाद क्लियर पॉलिसी और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इस काम में जुड़ी है। नरेन्द्र मोदी जी ने ये स्पष्ट कर दिया इस देश के किसी भी कोने में चाहे कश्मीर हो, उत्तर-पूर्व हो, या वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र हो, गैरकानूनी प्रवृत्ति नहीं चलेगी और इस पर कठोर हाथों से काम होगा। केन्द्र और राज्यों के बीच में अलाइनमेंट हुआ। स्टेट की कैपेसिटी में गवर्नमेंट, गवर्नेंस और पुलिसिंग में हमने सुधार किया। सीएपीएफ और स्टेट पुलिस का समन्वय बढ़ाया। एक्शनेबल इंटेलिजेंस को नीचे तक परकोलेट करने की व्यवस्था की और जिम्मेदारियां भी स्पष्ट कर दी। ऑल एजेंसी अप्रोच शुरू किया और सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि एनआईए, ईडी, इंटेलिजेंस एजेंसी, जैसे सभी नेटवर्क, फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम, पर हमने प्रहार किया। इफेक्टिव सरेंडर पॉलिसी लेकर आए। डेवलपमेंट और गवर्नेंस में हमने कोई वैक्यूम नहीं छोड़ा और अब पहले जहां राज्य की उपस्थिति नहीं थी, वहां आज राज्य की उपस्थिति है और नक्सलवाद की हार का सबसे बड़ा कारण यह है कि राज्य अब हर गांव में पहुंच चुका है, वहां पंचायत बन चुकी है। विकास के लिए हमने Whole of Government अप्रोच लिया और सुरक्षा नकेल कसने के लिए Whole of Agency अप्रोच लिया।

20 अगस्त-2019, 24 अगस्त-2024 और 31 मार्च- 2026 की तीन महत्वपूर्ण तारीखें हैं। 20 अगस्त 2019 को गृह मंत्रालय में एक मीटिंग हुई और पूरा पुलिस कोऑर्डिनेशन, मॉडर्नाइजेशन, रिटायर्ड नक्सलियों को पुलिस फोर्स में लेना, इनका कोऑर्डिनेशन खुफिया एजेंसी के साथ, ये सब 20 अगस्त को डिजाइन किया। छत्तीसगढ़ में विपक्षी पार्टी की सरकार थी जिसने सहयोग नहीं दिया। बिहार 2024 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था, महाराष्ट्र एक तहसील छोड़कर 2024 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। ओडिशा 2024 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। झारखंड एक जिला छोड़कर 2024 के पहले नक्सल मुक्त हो चुका था। सिर्फ छत्तीसगढ़ बचा हुआ था क्योंकि छत्तीसगढ़ की विपक्षी पार्टी की सरकार ने नक्सलवादियों को बचा कर रखा था। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी और दूसरे ही दिन, वहां पूरे समर्थन का भरोसा मिल गया। साझा रणनीति बनी और 24 अगस्त 2024 को हमने घोषित किया था कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूरे देश से समाप्त कर देंगे।

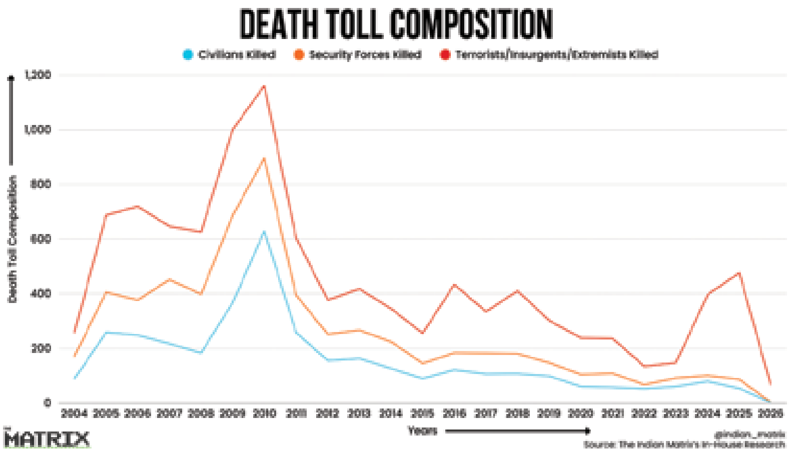

Source: The Indian Matrix's In-House Research

इसके बाद सुरक्षा घेरे में बढ़ोत्तरी की। प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 साल में 596 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बने। नक्सल प्रभावित जिले जो 2014 में 126 थे, आज सिर्फ दो बचे हैं। मोस्ट इफेक्टेड जिले 2014 में 35 थे, आज शून्य है। नक्सल घटनाएं दर्ज करने वाले पुलिस स्टेशन जो 350 थे, आज 60 हैं। पिछले 6 साल में 406 नए सीएपीएफ के कैंप बनाए, 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड बनाए, 400 बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ गाड़ियां हमारे जवानों को दी गई, पांच अस्पताल हमारे जवानों के लिए बनाए गए और कम्युनिकेशन की सारी व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई।

2024, 2025 और 2026 का संयुक्त आंकड़ा देखें तो तीन सालों में मारे गए नक्सली, 2026 के मार्च तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। 2218 गिरफ्तार हुए, उनको पकड़कर हमने जेलों में डाला है, अदालतों की शरण में ले गए और 4839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। विपक्ष संवाद की बात करता है। शासन का यही अप्रोच होना चाहिए जो वार्ता करना चाहता है, उसके साथ वार्ता करनी चाहिए और जो हमारे जवानों, किसानों, आदिवासियों, बच्चों पर गोली चलाता है, उसका जवाब गोली से देना चाहिए। हमने संवाद, सुरक्षा और समन्वय तीनों का उपयोग किया है। नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सटीक निगरानी और ढेर सारे टेलीफोन बिलों का विश्लेषण किया है। लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, मोबाइल फोन की गतिविधियां, साइंटिफिक कॉल लॉग्स, सोशल मीडिया एनालिसिस, फॉरेंसिक और तकनीकी संस्थानों की सहायता लेकर इस पूरे अभियान का गृह मंत्रालय ने नेतृत्व किया है। ड्रोन सर्वेलेंस, सैटेलाइट उपयोग, इमेजिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा एनालिसिस से ये सफलता प्राप्त हुई है।

बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में बिहार में 2022 में ऑपरेशन ऑक्टोपस चला। ऑपरेशन डबल बुल गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों में चला 8 से 25 फरवरी, 2022 में, तीनों जिले नक्सलवाद से मुक्त हो गए। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म झारखंड के सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूमि और खूंटी जिले में 1 से 3 सितंबर 2022 में चला। ऑपरेशन भीमबर्ग मुंगेर जिले के जून व जुलाई 2022 में चला। ऑपरेशन चक्रबांधा बिहार के गया और औरंगाबाद जिलों में 2022 में चला और ये सारे एरिया इससे मुक्त हो गए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा में 50 किलोमीटर लंबी और 37 किलोमीटर चौड़ी एक पहाड़ी

पर चला। वहां पर नक्सलियों ने अपना एक परमानेंट कैंप बनाया था और वहां 5 साल लड़ सकने के लिए हथियार, सोलर लाइट की व्यवस्थाएं, ढेर सारी आईडी बनाने की फैक्ट्रियां और 5 साल का अनाज था। इसके अलावा 400 से 500 कैडर वहां पर एकत्रित थे। 45 डिग्री टेंपरेचर पहाड़ पर पत्थर गर्म हो जाता था। शरीर में से 2 लीटर, 3 लीटर पसीना बह जाता था लेकिन जवानों ने उफ तक नहीं की और 21 दिन तक ऑपरेशन चला। 30 से ज्यादा माओवादी मारे गए, बाकी नीचे उतरते ही पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे गए या सरेंडर कर दिया और यह पूरा असला हमने जब्त कर लिया। इसी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मतलब बस्तर और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन का अंत कर दिया।

सेंट्रल कमिटी मेंबर और पोलित ब्यूरो मेंबर 2024 की शुरुआत में कुल 21 थे, जो इनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। एक पकड़ा गया है, सात सरेंडर हुए हैं, 12 मारे गए हैं और एक फरार है, उसके साथ भी वार्ता चल रही है। 21 के 21 सेंट्रल कमिटी मेंबर और पोलित ब्यूरो मेंबर समाप्त हो चुके हैं और उनकी केंद्रीय व्यवस्था टूट चुकी है। दंडकारण्य में 27 की स्टेट कमेटी थी, तीन अरेस्ट हुए, 20 सरेंडर हुए, 11 मारे गए और दो से बातचीत जारी है। दंडकारण्य की उनकी मुख्य स्टेट कमेटी थी, वो समाप्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमएमसी स्टेट कमेटी, तीन सरेंडर कर गए, तीन की ही बची थी। ओडिशा, चार बचे थे, एक सरेंडर हुआ, तीन मारे गए। ओएससी, ओडिशा, पांच ने सरेंडर किया, पांच मारे गए, 10 ही थे। डिस्टर्ब रीजन ब्यूरो, अरेस्ट एक हुआ, तीन मारे गए, एक फरार है। तेलंगाना में छह सरेंडर हो गए, तीन मारे गए, एक भी नहीं बचा है तो उनकी पोलित ब्यूरो मेंबर और सीएमसी पूरा समाप्त हो चुका है। हमने लक्ष्य रखा था कि 31 मार्च को देश को नक्सलवाद मुक्त करेंगे और हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में अब कोई संकोच नहीं है। बसव राजू उनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए, हिड़मा जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, गजुरल्ला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदारी सत्यनारायण रेड्डी 46 वर्षों से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्षों से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया। 46 वर्षों से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्षों से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्षों से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव मांझी देबू 36 वर्षों से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्षों से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। सभी मुख्य हथियारी माओवादी समाप्त हो चुके हैं। हमने ल्यूक्रेटिव पुनर्वास पॉलिसी को अपनाया है, जिसमें आत्मसमर्पण की प्रोत्साहन राशि 50,000 घोषित की गई है, जो सामूहिक सरेंडर पर दोगुना कर देते हैं। मोबाइल सबको सरकार की ओर से देते हैं। हथियार जमा कराने पर और मुआवजा देते हैं। पुनर्वासन केंद्र पर कौशल प्रशिक्षण व टूल किट का वितरण करते हैं। 10,000 प्रति माह 36 माह तक हम उनको देते हैं। सभी को मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की गिफ्ट दी है। नक्सल मुक्त पंचायत होते ही गांव के विकास के लिए ₹1 करोड़ दिया जाता है।

नक्सलियों ने 15000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो एसी चेंबर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन के तहत आर्टिकल लिखते हैं और वहां जीवन के जीवन उजड़ गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। जो अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं उनसे पूछा जाए कि 32 साल की आयु तक मेहंदी ना लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट की कौन चिंता करेगा? उसकी चिंता नरेन्द्र मोदी जी करेंगे और कोई नहीं। इन लोगों का अधिकार छीन लिया है, इसका हिसाब कभी न कभी देना पड़ेगा। जिन्होंने भी शब्द या प्रच्छन्न रूप से नक्सलियों का समर्थन किया है, वह सब इस पाप के उतने ही भागीदार हैं जितना बंदूक लेकर घूमने वाले हैं।

इनकी नौकरी और रोजगार के लिए हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं, कौशल केंद्र बनाए हैं। बारहवीं तक इनके बच्चों के लिए बारहवीं तक की मुक्त मुफ्त शिक्षा करी है। महिलाओं को 2 लाख और पुरुषों को 5 लाख के ऋण की व्यवस्था की है। वहां बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम के माध्यम से संस्कृति और खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। वहां अब 1 लाख 20 हजार कलाकारों ने बस्तर पंडुम में भागीदारी की और 5 लाख 50 हजार आदिवासी खेले हैं। जो इसको न्याय की लड़ाई कहते हैं, वो बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक में जाएं। पीड़ितों पर जुल्म ढाने वालों के लिए भाषण करने के लिए आपके पास बहुत समय है।

जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, तब एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी। एक नई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम खड़ा किया गया जो देश के कानून बनाता था। हर्ष मंदर इसके सदस्य थे, जिनके एनजीओ अमन वेदिका में शीर्ष नक्सली नेता की पत्नी को जिम्मेदारी दी गई थी और रिकॉर्ड है कि वह उन नक्सलियों में शामिल थी जिन्होंने अपहरण के केस अर्बन एरिया में किए थे। ये एनएससी देश का नीति निर्धारण करती थी। रामदयाल मुंडा कहते थे कि नक्सल ऑपरेशन जरूरत से ज्यादा कठोर है। इस प्रच्छन्न समर्थन ने ही नक्सलियों की हिम्मत बढ़ाई। नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा, ई ए एस शर्मा, ये सारे लोग सलवा जुडुम के केस के साथ भी जुड़े थे। जब सरकार की एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जो पीएम से भी ऊपर थी, उसके सदस्य अगर नक्सलवाद के समर्थक हों तो किस तरह से नक्सलियों का हौसला टूटेगा? कैसे टूटेगा? यह मुख्य विपक्षी पार्टी ने किया था। ये तो इतिहास है और जो लोग इस बात का विरोध करते हैं, आने वाले दिनों में सैकड़ों पुस्तकें लिखी जाएगी जो आपके कारनामों से भरी हुई होगीं।

नेता प्रतिपक्ष अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलियों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठनों ने हिस्सा लिया, इसका रिकॉर्ड है। 2010 में ओडिशा में लाडो सिकोका के साथ मंच पर दिखे। सिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और उन्हें माला भी पहनाई। 2018 में हैदराबाद में गुम्मांडी विठ्ठल राव उर्फ गद्दार से नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की जो विचारधारा के करीब रहे। मई 2025 में कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पीस के साथ मुलाकात की। आज जब 172 जवानों को मारने वाला हिडमा मारा गया तब इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे? हर घर से निकलेंगे हिडमा और इस वीडियो को नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं शेयर किया है।

नक्सलियों के समर्थकों ने 1970 से लेकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है। ये नरसंहार का समर्थन है और 20 हजार लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो मुख्य विपक्षी पार्टी की वामपंथी विचारधारा है। नक्सलियों के साथ रहते-रहते, ये पार्टी और उसके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा क्योंकि ये बात यहां रुकेगी नहीं, बल्कि जनता की अदालत में जाएगी। ■

बातचीत और कूटनीति ही समाधान

(पश्चिम एशिया संघर्ष पर लोकसभा में प्रधानमंत्री जी)

- **ऐसे अलग-अलग कारणों के चलते, भारत की चिंताऐं स्वाभाविक रूप से अधिक हैं। यह आवश्यक है कि इस संकट पर भारत की संसद की सर्वसम्मत और एकजुट आवाज दुनिया तक पहुंचे।**
- **भारत के युद्धग्रस्त और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ व्यापक व्यापारिक संबंध हैं, जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, वह दुनिया के अन्य देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है।**
- **भारत में कच्चा तेल, गैस और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं की बड़ी मात्रा होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से आती है, जबसे युद्ध आरंभ हुआ होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है।**
- **इसके बावजूद, सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति पर अधिक प्रभाव न पड़े और देश के आम परिवारों को कम से कम असुविधा हो, यही हमारा फोकस रहा है।**
- **भारत हमेशा से मानवता के हित में शांति की आवाज उठाता रहा है। बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है।**
- **हमारे प्रयास तनाव को कम करने और इस संघर्ष को समाप्त करने पर केंद्रित हैं।**
- **युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है, इसलिए**

पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक हैं। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर बहुत विपरीत असर हो रहा है, समस्त विश्व सभी पक्षों से इस संकट के शीघ्र समाधान का आग्रह कर रहा है।

यह क्षेत्र हमारे लिए एक और कारण से अहम है, क्योंकि लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं।

इन समुद्रों में चलने वाले वाणिज्यिक जहाजों में भारतीय चालक दल के सदस्यों की संख्या भी बहुत अधिक है।

भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर, बहुत ही विपरीत असर हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है।

भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। यह चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए यह रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं, उनमें भारतीय क्रू मेंबर की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग-अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि भारत की संसद से, इस संकट को लेकर एकमत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए।

जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ दो राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है।

संकट की स्थिति में देश-विदेश में भारतीयों की सुरक्षा बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक, 3 लाख 75 हजार से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है।

भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना-जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके, सरकार का यह प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। देश अपनी जरूरत के 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है, इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है, साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है।

आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डायवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी, ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था, वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है।

बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मैट्रिक टन से अधिक का स्ट्रैटेजिक पैट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है, वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफायनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सरकार अलग-अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास यह है कि जहां से संभव हो, वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं, ताकि हमारे मैरिटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहें। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों होर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी है।

संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में एथेनॉल का उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ एक डेढ़ परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच गए हैं। इसके कारण प्रतिवर्ष करीब साढ़े चार करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण ना होता, तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है, 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलो मीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी हैं। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा।

एनर्जी इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है और भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर असर के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है। आज भारत की इकॉनामी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, इससे भी देश को बहुत मदद मिली है। हम हर सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जहां भी जरूरत है, उस सेक्टर को आवश्यक सपोर्ट दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप भी बनाया है, ये ग्रुप हर रोज मिलता है और हमारे इंपोर्ट-एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है, और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता है।

सरकार और इंडस्ट्री के साझा प्रयासों से, हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल यह है कि युद्ध का खेती पर क्या प्रभाव होगा? देश के किसानों ने हमारे अन्न के भंडार भर रखे हैं, इसलिए भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न है। हमारा ये भी प्रयास है कि खरीफ सीजन की ठीक से बुआई हो सके। सरकार ने बीते सालों में आपात स्थिति से निपटने के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था भी की है। अतीत में भी हमारी सरकार ने दुनिया के संकटों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ने दिया था। कोरोना और उस समय को युद्धों के दौरान, उस समय भी ग्लोबल सप्लाई चेन में disruption आ गई थी। दुनिया के बाजार में यूरिया की एक बोरी 3000 रूपये तक पहुंच गई, लेकिन भारत के किसानों को वही बोरी 300 रूपये से भी कम कीमत पर उपलब्ध कराई गई।

देश के किसानों को इस प्रकार के संकटों से बचाने के लिए भी, बीते वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। पिछले एक दशक में देश में 6 यूरिया प्लांट शुरू किए गए हैं, इससे सालाना 76 लाख मीट्रिक टन से अधिक की यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी जुड़ी है। इस दौरान DAP और NPKS जैसी खाद का घरेलू उत्पादन भी करीब 50 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं तेल और गैस की तरह खाद के आयात को भी डायवर्सिफाई किया गया है। ऐसे ही DAP और NPKS के आयात के लिए भी, हमने अपने विकल्पों को विस्तार किया है।

सरकार ने देश के किसानों को मेड इन इंडिया नैनो यूरिया का विकल्प भी दिया है। सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 22 लाख से ज्यादा सोलर पंप दिए गए हैं, इससे भी डीजल पर उनकी निर्भरता कम हुई है। सरकार किसानों की हर संभव मदद करती रहेगी।

युद्ध का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि भारत में गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी। फिलहाल देश के सभी पावर प्लांट्स के पास पर्याप्त कोल स्टॉक्स उपलब्ध हैं। भारत ने लगातार दूसरे साल 100 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। पावर जेनरेशन से

लेकर पावर सप्लाई तक के हमारे सभी सिस्टम की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जा रही है, और सरकार की तैयारियों को रिन्यूएबल एनर्जी से मदद मिली है। बीते दशक में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देश ने बड़े कदम उठाए हैं। आज हमारी टोटल इंस्टॉल पावर जेनरेशन कैपेसिटी का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। हमारी कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावॉट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। बीते 11 वर्षों में देश ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी करीब 3 गीगावाट से बढ़ाकर 140 गीगावाट तक पहुंचाई है। बीते वर्षों में देश में करीब 40 लाख रूफटॉप सोलर लगे हैं, इसमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से भी लोगों को काफी मदद मिली है। गोबरधन योजना के तहत देश में आज 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट भी काम करना शुरू कर चुके हैं। ये सारे प्रयास आज देश के बहुत काम आ रहे हैं। सरकार ने भविष्य की तैयारी और बढ़ते हुए शांति एक्ट माध्यम से देश में न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है। कुछ ही दिन पहले स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे आने वाले वर्षों में 1500 मेगावाट नई हाइड्रो पावर कैपेसिटी जोड़ी जाएगी।

जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। पश्चिम एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। सभी से तनाव को कम करने और संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और होर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के माहौल में भी, भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।

भारत हमेशा से मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है, इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है।

जब ऐसे संकट आते हैं, तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रैटेजिक इंस्टालेशंस हो, सब की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है।

इस युद्ध के कारण, दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है, इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है, और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है, और बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है, हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। काला बाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले, एक्टिव हो जाते हैं, इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है, सभी राज्य सरकारें जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्यवाही करें। देश की हर सरकार और हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे, तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। ▪

मोदी जी ने सर्वाधिक समय तक सेवा का कीर्तिमान बनाया - डॉ. मोहन यादव

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत में सर्वाधिक समय तक शासन प्रमुख के रूप में सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है।

भारत की जनता प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति निरंतर स्नेह, विश्वास और समर्थन की भावना को अभिव्यक्त कर रही है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री श्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के शासन करने के रिकार्ड को पीछे छोड़ा है। उनके सार्वजनिक जीवन के 8931 दिन गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में दर्शाते हैं कि उन्होंने राष्ट्रप्रथम के सिद्धांत पर कार्य करते हुए अपनी भूमिका को यादगार बनाया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के ध्येय के साथ गरीब कल्याण से लेकर वैश्विक मंच पर हर क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने देश को विकास और सुशासन की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

संपूर्ण विश्व में भारत की साख बढ़ाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र निरंतर प्रगति, समृद्धि और वैभव के पथ पर अग्रसर बना रहेगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के दायित्व की वर्षवार अवधि की चर्चा करें तो वे वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 2002 में गुजरात विधानसभा के निर्वाचन के बाद वे दूसरी बार, वर्ष 2007 में तीसरी बार और वर्ष 2012 में चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। श्री मोदी वर्ष 2014 के लोक सभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर प्रधानमंत्री बने। वर्ष 2019 में पहले से भी बड़े जनादेश के साथ उनकी वापसी हुई और वे दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। श्री मोदी ने वर्ष 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन कर इतिहास रचा। ▪

देश और सीमाओं की रक्षा सर्वोपरि - डॉ. मोहन यादव

प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की ताकत से भाजपा ने देश को अजेय बनाने का संकल्प लिया।

- **कांग्रेस के अंदर विचारों और प्रशिक्षण की कमी, इसलिए अंतर्विरोध सामने आते हैं।**
- **दूसरे दलों में बड़े पद परिवारों में बंट जाते हैं।**

राजनैतिक जीवन में राष्ट्रसेवा और जनकल्याण के कार्य करते हुए अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशिक्षण का लाभ अद्भुत होता है। अगर भाजपा और कांग्रेस के बीच गतिविधियों की तुलना करें तो कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज के माध्यम से हुई। तब देश के बड़े-बड़े लोगों की कांग्रेस में सदस्यता थी और वे अंग्रेज अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते थे। कांग्रेस से जुड़े महामना पं. मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी सोमनाथ मंदिर को नकार रही थी। कांग्रेस के अंदर विचारों और प्रशिक्षण की कमी रही, इसलिए अंतर्विरोध सामने आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की तो तुर्किये किसके साथ खड़ा था, आज तुर्किये की क्या स्थिति है और वह किसका साथ दे रहा है सब जानते हैं। हम राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता और एकात्म मानववाद की बात करने वाले कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए देश और सीमाओं की रक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए सभी धर्म समान हैं, कभी किसी एक धर्म की बात नहीं करते हैं। यह गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने औपनिवेशवाद के अवशेषों को खत्म किया है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ और राजभवन का नाम लोकभवन किया गया। यह मूल विचारधारा है कि कार्यालय में, काम करने वालों में स्वभाषा का भाव और एकात्मता का दर्शन होना चाहिए। प्रशिक्षण के कारण ही जनसंघ में एकात्म का भाव जागृत हुआ और आज भी यह कार्यकर्ताओं के मन में है, जबकि कांग्रेस के इतने टुकड़े हुए कि उनके पास आज पहचान का संकट पैदा हो गया है।

संगठन का मूलभाव और काम करने का तरीका सदैव एक जैसा रहा है। आजादी के बाद से ही जनसंघ ने कश्मीर में लागू धारा-370 का विरोध किया था, और यह विरोध हमेशा वैचारिक दृष्टि से एक समान रहा है। यह निरंतरता पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी देखी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाने और अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए। भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है, सभी सेनाओं में कुल मिलाकर केवल 13 लाख से अधिक सैनिक हैं और पैरामिलिट्री बलों को भी जोड़ लिया जाए, तो यह संख्या करीब 40 लाख होती है। भारतीय सेना अपने प्रशिक्षण और अनुशासन के बल पर ही आज दुनिया में अजेय मानी जाती है। इसी तरह भाजपा के कार्यकर्ताओं के अनुशासन और अथक परिश्रम के कारण ही आजादी के बाद तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी है। पार्टी की ताकत हमारे प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं में है, जो किसी भी जिम्मेदारी को हाथ में लेते हैं और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। यही कार्यकर्ता बाद में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचते हैं। लोग इसे आश्चर्य से देखते हैं, लेकिन यह पार्टी की संस्कृति और कार्यशैली का परिणाम है। दूसरे दलों में नेतृत्व बड़े परिवारों के बीच बंट जाता है, लेकिन भाजपा संगठन में यह परंपरा कभी नहीं रही। भाजपा में नेतृत्व केवल कार्यकर्ताओं के परिश्रम और समर्पण से ही आता है। यही वह अंतर है जो भाजपा और दूसरे दलों के प्रशिक्षण और कार्यशैली में है। मध्यप्रदेश भाजपा संगठन कार्य की दृष्टि से पूरे देश में एक आदर्श संगठन के रूप में पहचाना जाता है। प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही भाजपा को निरंतर मजबूत बनाए रखते हैं, और यही कारण है कि हर क्षेत्र में अजेय स्थान हासिल करने में सक्षम हो रहे हैं। ■

भाजपा में विचारधारा स्थायी

- हेमंत खण्डेलवाल

- **भाजपा ने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया।**
- **भाजपा की कार्यपद्धति ने उसे दूसरे दलों से अलग बनाया।**

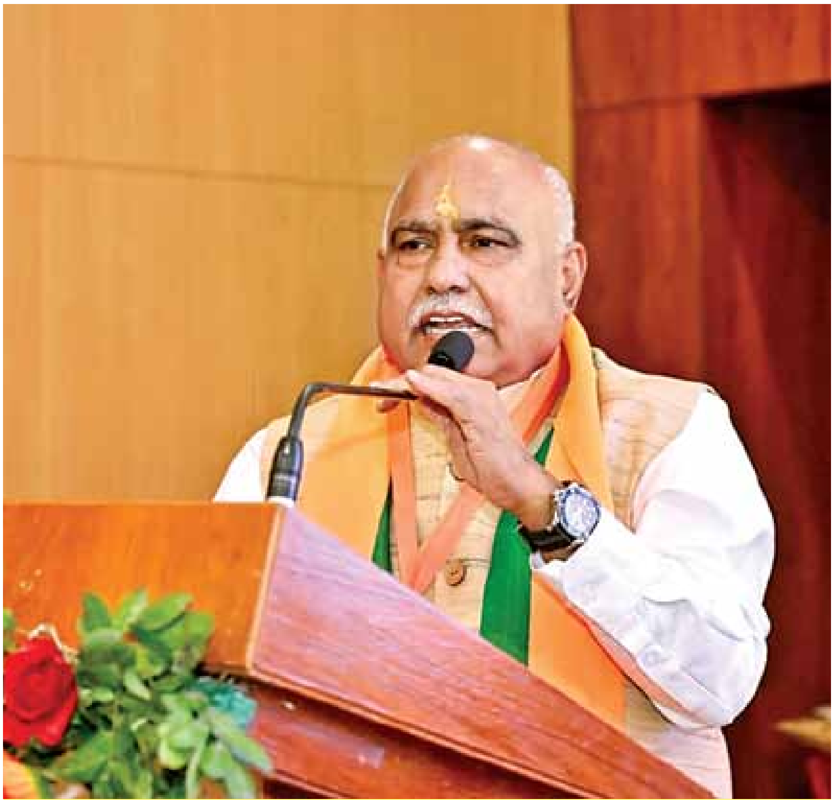

विचारधारा और कार्यपद्धति के बल पर भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना।

देश की राजनीति में वास्तव में दो ही दल ऐसे रहे हैं जिनकी स्पष्ट विचारधारा और कार्यपद्धति रही है एक कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचारधारा के कारण जनता से दूर होती गई और लगभग समाप्ति की ओर है। इसके अलावा अधिकांश दल विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि परिस्थितियों के आधार पर चलते रहे हैं। भाजपा ने विचारधारा और संगठनात्मक पद्धति को सर्वोपरि रखा है और इसी कारण पार्टी पूरे देश में सबसे आगे खड़ी है। हम सत्ता के लिए नहीं, बल्कि विचारधारा के तौर पर जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की राह पर तेजी के साथ बढ़ रहा है। जनसंघ के गठन के समय पार्टी ने संकल्प लिया था, जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाना, राम मंदिर निर्माण और तीन तलाक पर प्रतिबंध, उन पर कभी समझौता नहीं किया। वर्ष 1985 में भाजपा मात्र दो सीटों पर सिमट गई थी तब भी हमने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया और प्रशिक्षण के बल पर आगे बढ़ते हुए देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनी है। समय के साथ कार्यपद्धति में बदलाव आवश्यक होता है, लेकिन विचारधारा स्थायी रहती है। शुरुआती दौर में कार्यकर्ता कम थे, इसलिए सभी एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते थे और सीधे संवाद होता था। आज संगठन का विस्तार हुआ है, इसलिए समन्वय और संवाद के नए तरीके अपनाने की आवश्यकता है। संगठन में समन्वय, सहयोग और क्षमाशीलता की भावना आवश्यक है।

भाजपा का मूल स्वभाव सबको साथ लेकर चलने का है। आज के दौर में युवाओं की भूमिका बढ़ी है और नई तकनीक का उपयोग भी जरूरी है। महापुरुषों और नेताओं के त्याग और समर्पण के कारण ही संगठन मजबूत हुआ है।

प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मंडल स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशालाएं पूरी तरह कार्यकर्ताओं के सहयोग से आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं में अनुशासन और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि कार्यक्रमों की शुरुआत और समापन निर्धारित समय पर हो, क्योंकि यह भाजपा की कार्यपद्धति को दर्शाता है, जो हमें अन्य दलों से अलग पहचान दिलाता है। संगठन की सफलता का राज कार्यकर्ताओं के समर्पण में है, और यही कारण है कि कार्यशालाओं व प्रशिक्षण के माध्यम से संगठन की विचारधारा, कार्यपद्धति और समर्पण की भावना को और अधिक सशक्त बनाएंगे। प्रशिक्षण महाअभियान केवल कार्यकर्ताओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह पार्टी की विचारधारा और समर्पण की भावना को और अधिक सशक्त करने का एक अवसर है। सभी मिलकर इसे सफल बनाएंगे और भाजपा को और मजबूत करेंगे। ▪

भारत को आगे बढ़ाना लक्ष्य

- डॉ. महेन्द्र सिंह

पंडित दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाअभियान 2026
विषय वक्ता कार्यशाला
(जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, शहडोल संभाग)
9 मार्च 2026 | संभागीय भाजपा कार्यालय जबलपुर
भारतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश

प्रधानमंत्री जी के कार्यों से भारत वर्ष 2047 तक दुनिया का नेतृत्व करने को तैयार है।

- **पं. दीनदयाल जी व प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाएंगे भाजपा कार्यकर्ता।**
- **प्रशिक्षण पार्टी की विचारधारा और कार्यपद्धति आगे बढ़ाने के लिए है।**

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को मां माना है। इस मां के बेटों-बेटियों को कैसा होना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन हमें प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से मिला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें पार्टी को प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हुए विकसित भारत के सपने को साकार करना है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी धरोहर है। देश सबसे पहले है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से अग्रसर है। भारत के पास अमेरिका, चीन, आस्ट्रेलिया व रूस जैसे देशों से बहुत कम जमीन है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर भारत विश्व के विकसित राष्ट्रों की बराबरी करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2013 में भारत के प्रति व्यक्ति की आय की तुलना में वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति की आय की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग से बहुत सी बातें सीखेंगे और पं. दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने का कार्य करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संगठन की विचारधारा, कार्यपद्धति और देश निर्माण की दिशा में कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को पक्का मकान, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, निःशुल्क शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने पर काम कर रहे हैं। यह सब हम एक दृढ़ संकल्प के साथ कर रहे हैं, ताकि भारत न केवल आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, बल्कि हर नागरिक का जीवन बेहतर हो। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जब

ऊँचाई

अटल बिहारी वाजपेयी

ऊँचे पहाड़ पर,
पेड़ नहीं लगते,
पौधे नहीं उगते,
न घास ही जमती है।

जमती है सिर्फ बर्फ,
जो कफन की तरह सफेद और
मौत की तरह ठंडी होती है।
खेलती, खिलखिलाती नदी,
जिसका रूप धारण कर
अपने भाग्य पर बूँद-बूँद रोती है।

ऐसी ऊँचाई,
जिसका परस,
पानी को पत्थर कर दे,
ऐसी ऊँचाई
जिसका दरस हीन भाव भर दे,
अभिनन्दन की अधिकारी है,
आरोहियों के लिये आमंत्रण है,
उस पर झण्डे गाड़े जा सकते हैं,

किन्तु कोई गौरैया,
वहाँ नीड़ नहीं बना सकती,
ना कोई थका-माँदा बटोही,
उसकी छाँव में पलभर पलक ही झपका सकता है।

सच्चाई यह है कि
केवल ऊँचाई ही काफी नहीं होती,
सबसे अलग-थलग
परिवेश से पृथक,
अपनों से कटा-बँटा,
शून्य में अकेला खड़ा होना,
पहाड़ की महानता नहीं,
मजबूरी है।
ऊँचाई और गहराई में
आकाश-पाताल की दूरी है।

जो जितना ऊँचा,
उतना ही एकाकी होता है,
हर भार को स्वयं ही ढोता है,
चेहरे पर मुस्कानें चिपका,
मन ही मन रोता है।

जरूरी यह है कि
ऊँचाई के साथ विस्तार भी हो,
जिससे मनुष्य
ठूँठ-सा खड़ा न रहे,
औरों से घुले-मिले,
किसी को साथ ले,
किसी के संग चले।

भीड़ में खो जाना,
यादों में डूब जाना,
स्वयं को भूल जाना,

अस्तित्व को अर्थ,
जीवन को सुगन्ध देता है।

धरती को बौनों की नहीं,
ऊँचे कद के इंसानों की जरूरत है।
इतने ऊँचे कि आसमान को छू लें,
नये नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बो लें,

किन्तु इतने ऊँचे भी नहीं,
कि पाँव तले दूब ही न जमे,
कोई काँटा न चुभे,
कोई कली न खिले।

न वसंत हो, न पतझड़,
हो सिर्फ ऊँचाई का अंधड़,
मात्र अकेलेपन का सन्नाटा।

मेरे प्रभु!
मुझे इतनी ऊँचाई कभी मत देना
गैरों को गले न लगा सकूँ
इतनी रुखाई कभी मत देना।

मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत की जीडीपी 1.85 ट्रिलियन डॉलर थी, जो अब बढ़कर 4.58 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि 2029 तक भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर और 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी। उनका लक्ष्य है कि 2047 में जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर एक बनेगी।

प्रशिक्षण वर्ग पार्टी की विचारधारा और कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। बूथ कार्यकर्ता पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि बूथ जीतता है, तो पार्टी चुनाव जीतती है। कार्यकर्ता अपने-अपने जिलों में प्रशिक्षण लें और वहां की जनहितैषी योजनाओं के लाभार्थियों के आंकड़े और जानकारी पूरी तरह से रखें। कार्यकर्ताओं को यह जानना चाहिए कि हमारे जिले को भी सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे कार्यकर्ता गर्व महसूस करेगा और उसकी मेहनत को सही दिशा मिलेगी। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के अवसर प्रदान कर रही है, ताकि वे पार्टी की विचारधारा और कार्यपद्धति को और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकें। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि भाजपा एक संगठन आधारित राजनीतिक दल है, जो पूरी तरह से कार्यकर्ता आधारित है। भाजपा का कार्यकर्ता विचारधारा से प्रेरित है। हमें खुद को और तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि हम हर स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकें। प्रशिक्षण वर्ग का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को ऑलराउंडर बनाना है। भाजपा के संविधान और देश के संविधान के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं, तो पूरा विश्व उन्हें सुनता है। उसी प्रकार हमें भी इस प्रशिक्षण के माध्यम से हर स्तर पर प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है। सभी मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत और विकसित भारत बनाएंगे। ▪

“टीम इंडिया” सबसे बड़ी ताकत

सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए अहम सुझाव उभरती स्थिति का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भावी चुनौतियों से निपटने के लिए सतर्कता, तैयारियों और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

भारत के पास इस तरह के वैश्विक व्यवधान से निपटने का पहले का अनुभव है। कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए सामूहिक प्रयास, जब केंद्र और राज्यों ने ‘‘टीम इंडिया’’ के रूप में मिलकर आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार और दैनिक जीवन पर प्रभाव को कम करने के लिए काम किया। यही सहयोग और समन्वय की भावना वर्तमान परिस्थितियों से निपटने में भारत की सबसे बड़ी ताकत है।

हालात लगातार बदल रहे है, जिसके लिए निरंतर निगरानी और अनुकूल रणनीतियों की आवश्यकता है। 3 मार्च से एक अंतर-मंत्रालयी समूह सक्रिय है, जो दैनिक आधार पर स्थिति की समीक्षा कर रहा है और समय पर निर्णय ले रहा है। सरकार की प्राथमिकता आर्थिक और व्यापारिक स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्रदान करना है।

निर्णयों का प्रभावी कार्यान्वयन राज्य स्तर पर ही होता है। त्वरित और सुव्यवस्थित प्रतिक्रिया के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निरंतर संवाद और समन्वय, समय पर जानकारी साझा करने और संयुक्त निर्णय लेने की आवश्यकता है।

राज्यों को आपूर्ति श्रृंखलाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना तथा जमाखोरी व मुनाफाखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। व्यवधानों को रोकने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय करने और प्रशासनिक सतर्कता बनाए रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से उर्वरक के भंडारण और वितरण की निगरानी सहित कृषि क्षेत्र में पूर्व नियोजन की आवश्यकता है, ताकि आगामी खरीफ मौसम में किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

गलत सूचना के प्रसार और अफवाहों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, समय पर सटीक और विश्वसनीय जानकारी का प्रसार भय फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है। ऑनलाइन धोखाधड़ी और नकली एजेंटों के प्रति भी सतर्कता जरूरी है। नौवहन, आवश्यक आपूर्तियों और समुद्री संचालन से जुड़ी उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सीमावर्ती और तटीय राज्यों पर विशेष ध्यान देना होगा।

जनता का विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में आश्वासन नागरिकों में अनावश्यक भय फैलने से रोकने में मदद करेगा। जिन राज्यों के नागरिक पश्चिम एशिया में हैं, वे प्रभावित परिवारों की सहायता और समय पर जानकारी के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन सक्रिय करें, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें और जिला स्तर पर सहायता प्रणाली स्थापित करें।

भारत की आर्थिक और आपूर्ति प्रणालियों को मजबूत करने की दिशा में हाल के वर्षों में लिए, किए गए प्रयास वर्तमान परिस्थितियों में लाभकारी साबित हो रहे हैं। उद्योग और एमएसएमई के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना आवश्यक है, ताकि उनकी चिंताओं का समाधान हो और उत्पादन व रोजगार में स्थिरता सुनिश्चित हो सके। सभी स्तरों पर मजबूत समन्वय तंत्र की आवश्यकता है, जिनमें मुख्य सचिवों के स्तर पर नियमित समीक्षा और जिला स्तर पर निरंतर निगरानी शामिल है, ताकि बदलती परिस्थितियों का त्वरित और प्रभावी जवाब दिया जा सके।

तत्काल प्रतिक्रिया और दीर्घकालिक तैयारियों पर समान रूप से ध्यान देना होगा। राज्यों को जैव ईंधन, सौर ऊर्जा, गोबरधन पहल, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस के कनेक्शनों का विस्तार करने में तेजी लाना चाहिए। राज्यों के सक्रिय सहयोग के साथ घरेलू स्तर पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज बढ़ाने का बहुत महत्व है।

इस चुनौती से निपटना साझा जिम्मेदारी है और ‘‘टीम इंडिया’’ के रूप में मिलकर काम करते हुए देश इस स्थिति से सफलतापूर्वक निपट लेगा। ▪

अवसरों के केन्द्र मध्यप्रदेश से जुड़िए

- डॉ. मोहन यादव

- **राजस्थान की उद्यमशीलता और म. प्र. की संसाधन क्षमता ही बनाएगी सेंट्रल इंडिया को इंडस्ट्रियल पॉवर का सेंटर।**
- **सरप्लस पॉवर स्टेट म. प्र., अब बनेगा देश का ग्रीन, क्लीन एंड सोलर एनर्जी कैपिटल।**
- **म. प्र. में बन रहा देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पॉवर एंड रिन्युएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स।**

मध्यप्रदेश में बेहिचक कीजिए फुल इन्वेस्टमेंट, सरकार देगी फुल सपोर्ट। राजस्थान और मध्यप्रदेश हर मामले में है एक-दूजे के स्वाभाविक साझेदार।

मध्यप्रदेश और राजस्थान जुड़वा भाईयों की तरह हैं। दोनों राज्य मिलकर विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत तैयार कर रहे हैं। सिर्फ विरासतों और विविधताओं के ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी एक-दूसरे के स्वाभाविक साझेदार हैं। राजस्थान का विकसित टेक्सटाइल, जेम्स-एंड-ज्वेलरी और मध्यप्रदेश की ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन क्षमता, टेक्सटाइल पार्क एवं मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मिलकर एक सशक्त वैल्यू चेन तैयार कर सकते हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती-कालीसिंध-चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। ये परियोजना दोनों राज्यों की तस्वीर और तकदीर बदलेगी। लगभग 1 लाख करोड़ रूपए की इस परियोजना में दोनों राज्यों को मात्र 5-5 प्रतिशत राशि देनी होगी। इसकी 90 प्रतिशत लागत भारत सरकार देगी। दोनों राज्यों के बीच रोटी-बेटी का संबंध रहा है और अब पानी का संबंध भी बन गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे मधुरता से पूरे हो रहे हैं। राजस्थान के व्यापारियों ने देश-दुनिया में व्यापार-व्यवसाय में अपना नाम कमाया है। धन कमाने के लिए मन और बुद्धि चाहिए। राजस्थान के व्यापारियों ने अपनी क्षमता, युक्ति -बुद्धि और योग्यता से अपना लोहा मनवाया है। वर्तमान हालातों में कई तरह की चुनौतियां हैं, साथ ही हमारे पास आगे बढ़ने के स्वर्णिम अवसर भी हैं। कुछ साल पहले तक हमारे निवेशक खाड़ी देशों में निवेश के लिए जा रहे थे, लेकिन अब वहां स्थिति तेजी से बदल गई है। मध्यप्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में नियमों-कानूनों का सरलीकरण किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए 26 प्रकार की नई नीतियां लागू की हैं। अब स्पेस और एआई सेक्टर के लिए भी पॉलिसी लाने जा रहे हैं। मध्यप्रदेश, देश के सरप्लस बिजली स्टेट्स में से एक है। अब हम देश के ''ग्रीन, क्लीन एंड सोलर एनर्जी कैपिटल'' के रूप में उभर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस राज्य बनने के बाद अब मध्यप्रदेश की बिजली से दिल्ली में मेट्रो ट्रेन संचालित हो रही है। प्रदेश में लगभग 2 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट दर पर घरेलू बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। औद्योगिक विकास के साथ माइनिंग सेक्टर में भी तेज गति से कार्य हो रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोलने के लिए 1 रुपए में लीज पर जमीन दी जा रही है। मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। राज्य में 5 हजार से 50 हजार क्षमता की बड़ी गौशालाएं खोलने के लिए जमीन दी जा रही है। प्रति गौमाता अनुदान भी 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। पशुओं की नस्ल सुधार और चिकित्सा के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को निःशुल्क दूध के पैकेट बांटने के लिए योजना की शुरुआत की है।

एक समय था, जब लोग कहते थे कि मध्यप्रदेश में उद्योग टिक ही नहीं सकते, किंतु

आज मध्यप्रदेश भारत के सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में से एक है। मध्यप्रदेश की औद्योगिक विकास दर निरंतर बढ़ रही है। हमारी जीडीपी नई ऊँचाइयों को छू रही है। प्रदेश में निवेश की नई क्रांति आ रही है। उद्योगों की स्थापना एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए 6,104 करोड़ रूपये और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। मध्यप्रदेश का '' सिंगल विंडो सिस्टम-इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल'' देश के श्रेष्ठ डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म में गिना जाता है।

मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 अंतर्गत टेक्सटाइल एवं परिधान क्षेत्र को शामिल कर निवेशकों को आकर्षक इंसेंटिव प्रदान किए जा रहे हैं। अनेक प्रमुख कंपनियाँ मध्यप्रदेश में आ चुकी हैं और निवेश कर रही हैं। मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में भारत का पहला ''मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पॉवर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट'' विकसित किया जा रहा है।

होटल, हॉस्पिटल जैसे सेक्टर्स में बड़े निवेश पर कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश के रीवा में टाइगर सफारी और एयरपोर्ट की सौगात भी मिल चुकी है। राज्य की एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को प्रति फ्लाइट 15 लाख वीजीएफ दिया जा रहा है। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर भी हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पीएमश्री हेली सर्विस शुरू की गई है।

म. प्र. ने बिजली के समुचित बंटवारे के लिए उत्तरप्रदेश के साथ एक मॉडल तैयार किया है। मुरैना में प्लांट स्थापित कर 6-6 महीने बिजली उपयोग करने के लिए सहमति बनी है। पीकेसी परियोजना में दोनों राज्यों ने एक-दूसरे की बेहतरी के लिए निर्णय लिया है। सूखे क्षेत्र को पानी मिल जाए, तो लोगों की जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए यही समय है, मध्यप्रदेश और राजस्थान देश के साथ आगे बढ़ें। राजस्थान की उद्यमशीलता और मध्यप्रदेश की संसाधन क्षमता मिलकर सेंट्रल इंडिया को इंडस्ट्रियल पॉवर सेंटर बना सकते हैं। देश के दिल, असीम संभावनाओं और विकास अवसरों के केंद्र से जुड़िए, बेहिचक मध्यप्रदेश में निवेश कीजिए। मध्यप्रदेश में बेहतर नीतियां, बेहतर अवसर, बेहतर इन्सेंटिव, बेहतर इकोसिस्टम, बेहतर मार्केट लिंकेज और बेहतर ग्रोथ रेट के साथ हर कदम पर सरकार का फुल सपोर्ट मिलेगा। ■

संघ ने राष्ट्रभक्ति का अलख जगाया - डॉ. मोहन यादव

- **वर्ष 1925 में संघ के रूप में राष्ट्र विचार का रोपा गया पौधा आज वट वृक्ष बन गया है।**
- **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी से पहले ही ''आजाद भारत'' के स्वरूप की कल्पना कर ली थी।**
- **राष्ट्र विचार के भाव को जन-जन तक पहुंचाने के लिए फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है।**
- **हर क्षेत्र में कार्य कर रहे देशप्रेम से ओतप्रोत संगठन।**

वर्ष 1925 में पहले सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने भारत के आजाद होने से पहले ही कल्पना कर ली थी कि आजाद भारत का स्वरूप कैसा हो। वर्ष 1925 में ही कल्पना कर ली थी कि भारत की गुलामी का समय बहुत जल्दी जाने वाला है और भारत आजाद होने वाला है। आजाद भारत को एक सशक्त और शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए डॉ. हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। वर्ष 1925 में भारत के वर्तमान स्वरूप का आकार देने का प्रयास था। राष्ट्र विचार के भाव को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इस फिल्म को मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री किया गया है। मध्यप्रदेश के साथ कई राज्य इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने के लिए की गई। डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार अपने जीवनकाल में पं. मदनमोहन मालवीय, महात्मा गांधी सहित कई लोगों के संपर्क में रहे। हेडगेवार जी स्वयं क्रांतिकारी थे। संघ की स्थापना के पहले उन्होंने क्रांतिकारियों से संपर्क कर देश की आजादी के लिए कार्य किया। संघ पर जब पहली बार प्रतिबंध लगाया गया, तब भी संघ के स्वयंसेवकों ने अपनी राष्ट्रनिष्ठा का परिचय दिया। द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर जी ने अपने जीवनकाल में संगठन को खड़ा किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश प्रेम से ओतप्रोत संगठन है। साहित्य, चिकित्सा, मजदूर, किसान, विद्यार्थियों सहित अनेक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग संगठन बनाकर संघ देश को उसके परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। एआई से जो फिल्म बनी है, उसकी मैं बधाई देता हूं। हमारे प्रदेश में इसको हमने टैक्स फ्री भी किया है। यह फिल्म कई लोगों को सीखने के साथ अच्छे विषयों को लाने की परंपरा की शुरूआत है। हम सभी लोगों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित करेंगे। ■

जनता को मिलेगी राहत

हेमंत खण्डेलवाल

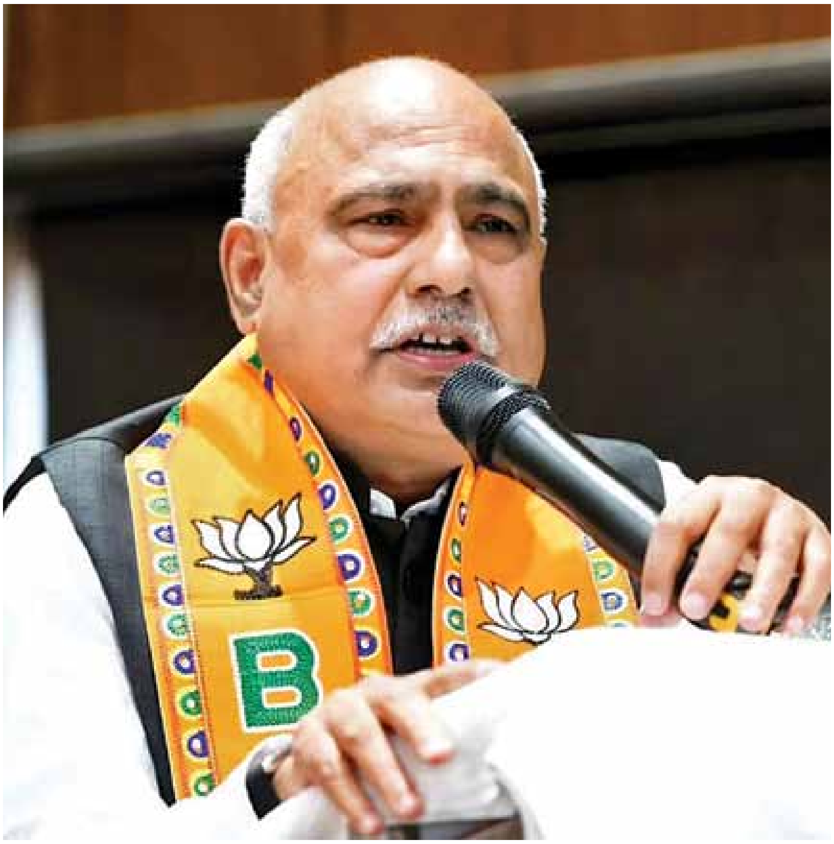

- **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी कटौती का निर्णय ऐतिहासिक।**
- **प्रधानमंत्री जी का वैश्विक संकट के बीच दूरदर्शी नेतृत्व देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगा।**
- **मोदी जी के नेतृत्व में भारत चुनौतियों को अवसर में बदलकर नई ऊर्जा के साथ उभरा।**
- **मोदी सरकार हमेशा जनता के हितों की रक्षा के लिए तत्पर।**
- **भारत की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत।**

पश्चिम एशिया में जारी वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय सराहनीय हैं। यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और समर्पण को और प्रगाढ़ करता है और देशवासियों को यह विश्वास दिलाता है कि सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। इस निर्णय में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 13 रुपये से घटाकर 3 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 10 रुपये से घटाकर शून्य रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता और संवेदनशील नेतृत्व का प्रतीक है, जो देश की जनता को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, भारत ने हर कठिन दौर में न केवल अपने पैरों पर खड़ा रहकर स्थिरता दिखाई है, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलकर नई ऊर्जा के साथ उभरा है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोत्तरी के चलते आने वाले समय में और भी वृद्धि की संभावना थी। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती कर देश की जनता को राहत देने का जो ऐतिहासिक कदम उठाया है, वह न केवल सरकार की सजगता को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि मोदी जी की सरकार हमेशा जनता के हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। इस निर्णय से न केवल आम आदमी को राहत मिलेगी, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। तेल की कीमतों में गिरावट से परिवहन क्षेत्र और अन्य उद्योगों को लाभ होगा, जिससे महंगाई पर भी नियंत्रण पाया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा जनता के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, यह उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हर संकट के समय में उत्कृष्ट नेतृत्व का परिचय दिया है। चाहे वह कोरोना महामारी का दौर हो या वैश्विक तेल संकट, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा देश को सही दिशा में मार्गदर्शन किया और संकटों को अवसरों में बदलने का कार्य किया। उनका यह कदम इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार हर स्थिति में जनता के साथ खड़ी है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के इस फैसले से न केवल आम जनता को राहत मिलेगी, बल्कि भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। ▪

कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता -डॉ. मोहन यादव

कृषक कल्याण वर्ष में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और कृषक कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करें।

प्रत्येक विधानसभा में आयोजित होंगे कृषि सम्मेलन।

- **विधानसभावार कृषि सम्मेलन के लिए कृषि विभाग देगा 5 लाख रुपए।**
- **लघु कृषकों को उन्नत खेती के लिए किराये पर उपलब्ध कराये जाएंगे कृषि यंत्र।**
- **डेढ़ साल में प्रदेश का दूध संकलन 25 प्रतिशत बढ़कर 12.50 लाख लीटर पहुंचा।**
- **पर्यटन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा मध्यप्रदेश।**

मध्यप्रदेश में दूध उत्पादन और पशुपालन की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्हें साकार करने के प्रयास सफल हो रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले डेढ़ साल में प्रदेश का दूध कलेक्शन 25 प्रतिशत बढ़ा है। अब प्रदेश में प्रतिदिन 12.50 लाख लीटर दूध कलेक्शन किया जा रहा है। दूध का मूल्य भी 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। इससे दुग्ध उत्पादकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने और क्षेत्र में नरवई प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ट्रैक्टर-ट्रॉली और भूसे की मशीन उपलब्ध करवा रही है। राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क दूध वितरण के लिए माता यशोदा योजना शुरू करने की पहल की है।

धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने होम स्टे की योजना शुरू की है। होम स्टे संचालकों के लिए 20 लाख रुपये तक की आय जीएसटी से मुक्त रखी गई है। लघु-कुटीर उद्योग के क्षेत्र में शहद उत्पादन से किसान लाभ कमा रहे हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हैक्टेयर करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं।

विधानसभा क्षेत्र में कृषि यंत्रों की दुकानें खुलेंगी, जिनसे लघु कृषकों को खेती के लिए किराये पर यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। विधायक अपने क्षेत्र में 4 से 5 कृषि सम्मेलन करें, इसके लिए कृषि विभाग ने प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 लाख रुपए आवंटित करने का निर्णय किया है। इन प्रयासों से कृषि कल्याण के लिए सकारात्मक वातावरण बनेगा। किसान सौर बिजली उत्पादन की सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। लघु-कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कार्य करें। ■

लक्ष्य, मंजिल “विकसित भारत” - पीएम मोदी

भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, भारत खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है।

कई वैश्विक संकटों के बावजूद, दुनिया के नेता और विशेषज्ञ भारत की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं।

अगर आप भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको भारत में होना होगा।

- **भारत सिर्फ प्रगति ही नहीं कर रहा है, भारत अब ‘अगले स्तर’ पर जा रहा है।**
- **भारत यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि उसके किसान और नागरिक वैश्विक चुनौतियों के बोझ से सुरक्षित रहें।**

12 मार्च, 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी। ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक टर्निंग प्वाइंट था। क्योंकि इस यात्रा ने देश के कोने-कोने को एक लक्ष्य के साथ जोड़ दिया था और ये लक्ष्य था- भारत की आजादी। इस ऐतिहासिक यात्रा के करीब 100 वर्षों के आसपास भारतीय फिर एक नई यात्रा पर निकले हैं। ये यात्रा है- ‘‘विकसित भारत की यात्रा।’’ लक्ष्य और मंजिल एक है - विकसित भारत।

21वीं सदी का ये कालखंड ‘ना भूतो न भविष्यति’ जैसा है। एक तरफ युद्ध की विभिषिका है, सप्लाई चेन तहस-नहस हो रही है संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्रासंगिकता पर सवालिया निशान लग रहा है, और ऐसे कालखंड में भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया इतिहास के जिस महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ी है, उस पड़ाव पर जिस देश का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है- वो है भारत। वर्तमान में इतने सारे संकटों के बीच दुनिया का हर गंभीर नेतृत्व, हर जानकार भारत को लेकर बहुत उम्मीदों से भरा हुआ है।

फिनलैंड के प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि अब दुनिया की दिशा, ग्लोबल साउथ तय करेगा और उस दिशा को निर्धारित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति होगा - भारत।

कनाडा के पीएम कार्नी ने कहा - अगले तीन दशकों में दुनिया की Economic Gravity जिस सेंटर की ओर शिफ्ट हो रही है, उसका नाम भारत है।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों मानते हैं - भारत दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों को सुलझाने वाला एक इनएविटेबल पार्टनर बन चुका है।

टेक वर्ल्ड और अर्थ जगत के ग्लोबल लीडर्स के बयानों का निचोड़ निकालें तो एक ही भाव सामने आता है, अगर आप भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको भारत से जुड़ना ही होगा, भारत में होना ही होगा।

अभी-अभी भारत ने टी-ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीता है। हर कोई खुश है और भारत में तो क्रिकेट का मामला ऐसा है कि अगर किसी ऑफिस में कोई करोड़ों की बात चलती हो, कोई बढ़िया

प्रेजेंटेशन चल रहा होता है विदेश के मेहमान प्रेजेंटेशन कर रहे हों फिर भी वो जरा स्लाइड से नजर हटा कर के वो स्कोर क्या है, देखता है। और कोई न कोई तो पूछ ही लेता है- भाई स्कोर क्या हुआ ठीक ऐसी ही स्थिति, आज भारतीय अर्थव्यवस्था की है। आज हर कोई इकॉनॉमी की रनिंग कमेंट्री चाहता है। भारत की इकॉनॉमी का पिछले महीने क्या स्टेटस था आज क्या हाल है ये सब जानने के लिए देशवासी उत्सुक रहते हैं। ये दिखाता है कि आज भारतीयों की एस्पिरेशन्स और आत्मविश्वास किस स्तर पर हैं। यही, दुनिया के भारत पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण भी है।

निश्चित तौर पर जब इतनी सारी उम्मीदें जुड़ी हों, दुनिया की नजर हमारे देश पर हो तो हम सभी की जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है।

आज का भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा। भारत खुद को Next Level पर ले जा रहा है। आज देश में Next Generation फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हम नेक्स्ट जेनरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहे हैं UPI ने Digital Payments को Next Phase में पहुँचा दिया है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज real-time digital payments करने वाला देश बना है।

भारत आज नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहा है, वो Reform एक्सप्रेस पर सवार है। कभी भारत में कई काम, कई निर्णय Next to Impossible माने जाते थे, आज भारत वो निर्णय भी ले रहा है। कभी कहा जाता था कि Article 370 हटाना नामुमकिन है। लेकिन आज जम्मू-कश्मीर में Article 370 की दीवार गिर चुकी है। कभी लगता था कि देश में सबका बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना असंभव है। लेकिन आज 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खातों ने ये संभव कर दिखाया है। कभी लगता था कि ट्रिपल तलाक को खत्म करना असंभव है। लेकिन आज मुस्लिम बहनों को इस अन्याय से मुक्ति मिली है। कभी महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में तैंतीस परसेंट आरक्षण भी असंभव लगता था। लेकिन आज इसके लिए कानून बन चुका है। कभी अंतरिक्ष और advanced technology को लेकर भी भारत की लिमिट्स बताई जाती थीं। लेकिन आज मून मिशन, Semiconductor Mission, क्वांटम मिशन, ये सब भारत को Next फ्रंटियर of Technology की ओर ले जा रहे हैं।

आज का भारत केवल सपने नहीं देख रहा। भारत उन्हें सच कर रहा है। इसीलिए आज दुनिया कह रही है- India is not just progressing. India is moving to the Next.

देश के विकास का एक बहुत बड़ा आधार होता है कि हम चुनौतियों से कैसे मुकाबला कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि वैश्विक परिस्थितियाँ अचानक बदलती हैं। बीते वर्षों में पहले कोरोना की आपदा देखी फिर रूस-यूक्रेन का संकट देखा और अब हमारे बहुत पास में ही एक और बड़ा युद्ध चल रहा है। इस युद्ध ने पूरे विश्व को बहुत बड़े ऊर्जा संकट में धकेल दिया है।

ऐसी विकट परिस्थितियों में बहुत अहम है कि एक देश के तौर पर हम इसका कैसे मुकाबला करते हैं। संकट काल एक प्रकार से, पूरे राष्ट्र की परीक्षा होती है। शांति के साथ धैर्य के साथ हमें परिस्थितियों से निपटना होता है जनविश्वास बढ़ाकर जनता को जागरूक करते हुए, हमें चलना होता है। और इसमें हर किसी की भूमिका होती है। हर राजनीतिक दल की, मीडिया की, सामाजिक संस्थाओं की, इंडस्ट्री की, युवाओं की गांव की शहर की हर किसी की भूमिका अहम होती है। और हमने कोरोना काल में देखा है जब सब मिलकर चलते हैं तो संकट से मुकाबले के लिए देश का सामर्थ्य कई गुणा बढ़ जाता है। आज देश के सामने एक और चुनौती है और इसलिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्य निभाने होंगे।

LPG को लेकर कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद तो एक्सपोज हो ही रहे हैं और देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं।

आज युद्ध से जो वैश्विक संकट आया है उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई शिकार है, भारत सरकार भी, इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। और हम अलग-अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। बीते दिनों, दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं से मेरी इसको लेकर बातचीत हुई है। सप्लाई चेन में जो बाधाएं आई हैं, उससे हम कैसे पार पाएं, इसके लिए भी निरंतर प्रयास चल रहे हैं।

भारत के तेज विकास के लिए अलग-अलग एनर्जी सोर्सेस को बढ़ावा देना निरंतर जरूरी रहा है। और इसको मजबूत करने के लिए दो स्तरों पर एक साथ काम किया है। पहला देश में एनर्जी एक्सेस बढ़े इंफ्रास्टक्चर तैयार किया। और दूसरा- Energy के लिए हमें सिर्फ विदेशों पर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए Energy सेक्टर में आत्मनिर्भरता पर बल दिया।

साल 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ LPG कनेक्शन थे। यानि देश के करीब-करीब आधे परिवारों पास ही LPG कनेक्शन था। आज दोगुने से भी अधिक यानि करीब 33 करोड़ घरेलू LPG कनेक्शन हैं। बीते 11 वर्षों में हमने अपनी बॉटलिंग कैपेसिटी को दोगुना किया है। डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर भी 13 हजार से बढ़कर 25 हजार से अधिक हो गए हैं 2014 में देश में सिर्फ 4 LNG Terminals थे, आज इनकी संख्या भी बढ़कर दोगुनी हो गई है। गैस पाइपलाइन जो करीब साढ़े तीन हजार किलोमीटर होती थी उसको 10 हजार किलोमीटर तक विस्तार दिया है। क्योंकि करीब 60 परसेंट LPG विदेशों से आती है इसलिए देश के बड़े पोर्टस पर इंपोर्ट टर्मिनल कैपैसिटी भी बहुत बढ़ाई गई है।

साल 2014 से पहले तक देश में सिर्फ 25-26 लाख घरों में ही, पाइप से सस्ती गैस यानि PNG की सुविधा थी। आज ये संख्या भी सवा करोड़ से अधिक पहुंच गई है। 2014 में देश में CNG पर चलने वाली गाड़ियां भी 10 लाख से ज्यादा नहीं थी। आज ये संख्या 70 लाख से अधिक है। और ये तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते दशक में देश के 600 से अधिक जिलों में City Gas Distribution network स्थापित किए गए हैं।

इस वैश्विक संकट ने एक बार फिर दिखाया है कि किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना इतना अधिक जरूरी क्यों है। इसलिए ही बीते वर्षों में हमने भारत को एनर्जी सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बनाने के लिए होलिस्टिक तरीके से काम किया है।

पेट्रोलियम पर निर्भरता को कम करने के लिए हमने इथेनॉल पर, बायोफ्यूल पर बल दिया। 2014 से पहले देश में सिर्फ एक-डेढ़ परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी ही थी। आज हम पेट्रोल में 20 परसेंट इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। अगर ये काम न किया होता तो हमें बीते 11 वर्षों में करीब 18 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल विदेशों से खरीदना पड़ता। आज की स्थिति देखें तो इथेनॉल के कारण हमें प्रतिवर्ष करीब साढ़े चार करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। यानि करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए की बचत तो देश को सिर्फ इसी से हुई है।

भारत में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा कंज्यूमर रेलवे है। देश में रेलवे लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 60 साल पहले शुरू हुआ था। बावजूद इसके 2014 तक सिर्फ 20 परसेंट रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन ही हो पाया था। बाकी रेलवे रूट्स पर हजारों डीजल इंजन चला करते थे। आज भारत में ब्रॉडगेज नेटवर्क का करीब-करीब 100 percent बिजलीकरण हो चुका है। इससे, साल 2024-25 में ही भारतीय रेलवे ने करीब 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत की है। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन न हुआ होता तो हर वर्ष इतना डीजल बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता। ऐसे ही, मेट्रो का नेटवर्कबढ़ाया, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर फोकस किया।

ऐसे ही एक और बहुत बड़ा काम रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर किया है। आज टोटल installed power generation capacity का आधा हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आता है। कुल रिन्यूएबल क्षमता आज 250 गीगावाट के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई है। 2014 में भारत की सोलर पावर कैपेसिटी सिर्फ दो गीगावॉट थी, आज ये करीब चालीस गुणा बढ़कर hundred and thirty गीगावॉट हो चुकी है। घरेलू उपयोग में गैस के अलावा बिजली अधिक से अधिक काम आए इसके लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू की गई। अभी तक इस स्कीम के तहत करीब 30 लाख परिवारों ने रूफटॉप सोलर लगाए हैं।

इसके अलावा गोबरधन स्कीम पर भी काम किया। इसके तहत Compressed Biogas बनाने पर काम किया गया। अभी तक देश में 100 से अधिक प्लांट चालू हो चुके हैं और 600 से ज्यादा पर काम चल रहा है।

पेट्रोल-डीजल के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में भी व्यापक प्रयास किया है। 2014 से पहले भारत के पास strategic पेट्रोलियम रिजर्व यानि संकट के समय के लिए कच्चा तेल स्टोर करने की कैपेसिटी ना के बराबर थी। आज 50 लाख टन से अधिक का strategic पेट्रोलियम रिजर्व है। और इससे भी अधिक कैपेसिटी पर काम चल रहा है। बीते दशक में रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी सालाना 40 मिलियन टन से अधिक की वृद्धि की है। तभी भारत आज दुनिया के सबसे बड़े refining hubs में से एक बना है। यानि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर और कितनी बड़ी दिशाओं में काम कर रहे हैं। ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है, उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। जैसे संगठित होकर कोविड के संकट से देश को बाहर निकाला था उसी प्रकार इस वैश्विक संकट को भी पार कर लेंगे। जहां तक सरकार का प्रश्न है, किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा।

यूक्रेन युद्ध से लेकर आज तक हमने ये देखा है कि कैसे इसका प्रभाव वैश्विक मार्केट से लेकर दुनिया के नागरिकों पर पड़ता रहा है। लेकिन भारत सरकार का हमेशा से हर संभव प्रयास रहा है कि युद्ध से बनी परिस्थितियों का बोझ भारत के नागरिकों पर ना पड़े। जैसे जब रूस-यूक्रेन का संकट बढ़ा था, तो उस कालखंड में फर्टिलाइजर की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। इसके बावजूद यूरिया की जो बोरी अंर्तराष्ट्रीय बाजार में 3000 रुपए में मिल रही थी वो हमने अपने किसानों को सिर्फ 300 रुपए में दी थी। इस बार भी हर संभव प्रयास होगा कि देश के किसान, देश के नागरिकों के जीवन पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े।

बीता एक दशक, आत्मनिर्भरता के साथ-साथ संवेदनशील गवर्नेंस का भी रहा है। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा, वहां रहने वाले लोग दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकारों की सोच से भी दूर रहे। लेकिन हमारी सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों को गवर्नेंस की प्राथमिकताओं से जोड़ा। आज इन इलाकों में हाउसिंग हो, रोड्स हों, स्कूल-हॉस्पिटल हों ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए ही Aspirational District योजना, Aspirational ब्लाक योजना पीएम जनमन योजना जैसी स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं।

कांग्रेस की सरकारों का एक बहुत बड़ा पाप ये भी रहा कि उन्होंने देश के एक बड़े हिस्से को माओवादी आतंक की आग में जलने के लिए छोड़ दिया था। देश के करीब-करीब हर बड़े राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा माओवादी आतंक की गिरफ्त में था।

बीते सालों में देश ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। हम बुलंद हौसले के साथ आगे बढ़े। और इसका नतीजा आज देश देख रहा है। साल 2013 में 180 से अधिक जिले माओवादी आतंक से प्रभावित थे। आज माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों की संख्या सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है।

बीते एक साल में ही 2100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है 900 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, और जो हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे 300 से अधिक कटट्र नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसका परिणाम ये हुआ कि जो इलाके कभी डर के साए में जीने को मजबूर थे वहां आज विकास की नई ऊर्जा का संचार हो रहा है।

भारत आज जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रगति की गति को रोकना असंभव है। 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा आज next level पर है। मैं जानता हूं कि जब एक सपना पूरा होता है तो नए सपने, नई आकाक्षाएं जन्म लेती हैं। मैं इसे बोझ नहीं मानता, बल्कि जनता के विश्वास की पूंजी मानता हूं। हां...देश में मेरे कुछ ऐसे शुभचिंतक हैं जिनको लगता है कि उम्मीदों के बोझ तले मोदी कभी तो दबेगा, कभी तो कुचला जाएगा लेकिन उनकी नीयत इतनी खोटी है, कि उनकी उम्मीदें पूरी ही नहीं होती, और देशवासियों का आशीर्वाद जब तक है तब तक ये पूरी होंगी भी नहीं। अब सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों की आशाएं और आकांक्षाएं ही पूरी होंगी। भारत हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा भारत हर हाल में विकसित बनेगा। ■

140 करोड़ भारतीयों की एकता पर भरोसा

- **जैसे हमने पहले 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से हर संकट को पार किया है, वैसे ही इस बार भी हम सब मिलकर विजय हासिल करेंगे।**
- **'जल संचय अभियान' के तहत, देश भर में लगभग 50 लाख आर्टिफिशियल वॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं।**
- **अमृत सरोवर अभियान के तहत, देश भर में लगभग 70,000 अमृत सरोवर बनाए गए हैं।**
- **ज्ञान भारतम सर्वे हमारी महान संस्कृति और समृद्ध विरासत से जुड़ा है। इसका उद्देश्य देश भर में मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है।**
- **हाल ही में MY Bharat ने एक बजट क्वेस्ट का आयोजन किया। इसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को बजट प्रोसेस और पॉलिसी मेकिंग से जोड़ना था।**
- **हमारे देश के युवा अब ऐसे स्पोर्ट्स को अपना रहे हैं जो पहले उतने पॉपुलर नहीं थे।**
- **मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि चीनी का सेवन कम करें. . . और जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमें खाने के तेल का उपयोग भी 10 प्रतिशत तक घटाना चाहिए।**
- **मछुआरे भाई-बहन सिर्फ समुद्र के योद्धा ही नहीं हैं, वे आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव भी हैं।**
- **आज, फिशरीज और seaweed के फील्ड में नित नए इनोवेशन हो रहे हैं, और हमारे मछुआरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।**

132 वां संस्करण
श्री नरेंद्र मोदी जी
मन

खाड़ी देशों का बेहद आभारी हूँ, जो 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को हर तरह की मदद दे रहे हैं।

सभी नागरिक सतर्क रहें और अफवाहों में न आएँ सिर्फ सरकार की ओर से मिल रही नियमित जानकारी पर ही भरोसा करें।

- **"एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत, पूरे देश में लाखों पेड़ लगाए गए हैं।**
- **आज "पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना" का असर देश के हर कोने में देखा जा रहा है।**

मार्च का महीना, वैश्विक स्तर पर बहुत ही हलचल भरा रहा है। हम सबको याद है कि पूरा विश्व भूतकाल में कोविड के कारण एक लंबे समय तक अनेक समस्याओं से गुजरा था। हम सभी की अपेक्षा थी कि कोरोना के संकट से निकलने के बाद दुनिया नए सिरे से प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी। लेकिन, दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार युद्ध और संघर्ष की परिस्थितियाँ बनती चली गईं। वर्तमान में हमारे पड़ोस में एक माह से भीषण युद्ध चल रहा है। हमारे लाखों परिवारों के सगे-संबंधी इन देशों में रहते हैं, खासतौर पर खाड़ी देशों में काम करते हैं। मैं Gulf Countries का बहुत आभारी हूँ, वे ऐसे एक करोड़ से ज्यादा भारतीयों को वहाँ पर हर प्रकार की मदद दे रहे हैं।

जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है, वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग-अलग

देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले एक दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है।

निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है, इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देशवासी जागरूक रहें, अफवाहों के बहकावे में ना आएं। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। हमने 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से पुराने संकटों को हराया था, इस बार भी हम सब मिलकर के इस कठिन हालत से बहुत ही अच्छी तरह बाहर निकल जाएंगे।

भारत की ताकत यहाँ के कोटि-कोटि लोगों में निहित है । 'मन की बात' में ऐसे प्रयास के बारे में बताना चाहता हूं, जो देशवासियों की जनभागीदारी की भावना को दर्शाता है। ये प्रयास है - ज्ञान भारतम सर्वे, जिसका संबंध हमारी महान संस्कृति और समृद्ध विरासत से है । इसका उद्देश्य देशभर में मौजूद manuscripts यानि पांडुलिपियों के बारे में जानकारी जमा करना है । इस सर्वे से जुड़ने का एक माध्यम, ज्ञान भारतम ऐप है। आपके पास अगर कोई manuscript है, पांडुलिपि है, या उसके बारे में जानकारी है, तो उसकी फोटो 'ज्ञान भारतम ऐप' पर जरूर साझा करें । हर entry से जुड़ी जानकारी को दर्ज करने से पहले उसकी पुष्टि भी की जा रही है । मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक हजारों manuscripts पांडुलिपि लोगों ने शेयर की हैं। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के नामसाई के चाओ नंतिसिन्ध लोकांग जी ने ताई लिपि में पांडुलिपियाँ साझा की हैं। अमृतसर के भाई अमित सिंह राणा ने गुरुमुखी लिपि में पांडुलिपि शेयर की हैं। यह हमारी महान सिख परंपरा और पंजाबी भाषा से जुड़ी लिपि है। कुछ संस्थाओं ने palm leaf यानि ताड़ के पत्तों पर लिखी manuscripts दी हैं। राजस्थान के अभय जैन ग्रंथालय ने copper plates पर लिखी बहुत पुरानी पांडुलिपियाँ share की हैं। वहीं, लद्दाख की Hamis Monastery ने तिब्बती में बहुमूल्य पांडुलिपियों के बारे में जानकारी दी है। यह survey, जून के मध्य तक जारी रहने वाला है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपनी संस्कृति से जुड़े पहलुओं को सामने लाएं और share करें।

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। देश के युवा की ताकत जब राष्ट्र निर्माण में जुड़ती है, तो बहुत बड़ी मदद मिलती है। राष्ट्र निर्माण के इस दायित्व को निभाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, मेरा युवा भारत यानि MY Bharat संगठन। ये संगठन देश के युवाओं को अलग-अलग positive गतिविधियों से जोड़ रहा है। हाल ही में MY Bharat द्वारा Budget Quest का आयोजन किया गया। इसका मकसद था देशभर के युवाओं को budget प्रक्रिया और नीति निर्माण से जोड़ना। इससे जुड़ी quiz में देशभर से करीब 12 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। Quiz के बाद करीब एक लाख साठ हजार प्रतिभागियों को निबंध प्रतियोगिता के लिए चुना गया। मुझे इनमें से कुछ निबंध पढ़ने का अवसर भी मिला। इनसे पता चलता है कि युवा साथी देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए कितना तत्पर हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट से कोटला रघुवीर रेड्डी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सौरभ बैसवार और बिहार के गोपालगंज से सुमित कुमार ने किसान कल्याण से जुड़े topic पर लिखा है। पंजाब के मोहाली से आंचल और ओडिशा के केंद्रपाड़ा से ओम प्रकाश रथ ने, women–led development को आगे बढ़ाने के तरीकों पर अपने विचार प्रकट किए हैं।

हरियाणा के यमुनानगर से प्रथम बरार ने लिखा है कि Green और Clean Bharat ही समृद्ध भारत का मार्ग है। इससे उनकी गहरी सोच का पता चलता है। दिल्ली के शंख गुप्ता का सुझाव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए और अधिक प्रयास होने चाहिए। युवा साथियों ने skill development और ease of doing business पर भी अपने विचार साझा किए हैं। मैं उन सभी युवाओं की सराहना करता हूं, जो अपने ideas share कर रहे हैं। ये विचार देश को आगे ले जाने में बहुत अहम हैं ।

देशभर के cricket fans के लिए यह महीना जोश और उत्साह से भर देने वाला रहा है। जब भारत ने T20 World Cup में ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो देश में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी team की इस शानदार सफलता पर हम सभी को बहुत गर्व है। पिछले महीने के आखिर में कर्नाटक के हुबली में एक बहुत ही रोचक मुकाबला देखने को मिला, इस मुकाबले को जीतकर जम्मू-कश्मीर की cricket team ने रणजी trophy को अपने नाम कर लिया। सबसे खुशी की बात है कि करीब 7 दशकों के लंबे इंतजार के बाद इस team ने अपना पहला रणजी खिताब हासिल किया। यह अभूतपूर्व सफलता खिलाड़ियों के कई बरसों के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। टीम के कप्तान पारस डोगरा ने अद्भुत कौशल दिखाया। अपने नेतृत्व से इस जीत में उन्होंने अहम योगदान दिया। आज देश में कश्मीर के युवा गेंदबाज आकिब नबी के प्रदर्शन की भी चर्चा हो रही है, जिन्होंने रणजी सीजन में 60 विकेट लिए हैं। इस जीत से टीम के खिलाड़ी और coaching staff के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के लोग बहुत रोमांचित हैं। Cricket के मैदान में इस शानदार प्रदर्शन के बाद वहां के युवाओं में खेलों के प्रति उत्साह और बढ़ गया है। आने वाले समय में यह कई युवाओं को sports को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। जम्मू-कश्मीर के लोगों में खेलों को लेकर गजब का जज्बा रहा है। अब यह बड़े खेल आयोजनों का हब भी बनता जा रहा है। Khelo India Winter Games के लिए गुलमर्ग तो पहले ही अपनी पहचान बना चुका है। Football जैसे sports भी यहां के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ियों की जीत का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।

जो खेलेगा, वो खिलेगा। हमारे देश के युवा, अब उन खेलों को भी खूब अपना रहे हैं, जो पहले उतने लोकप्रिय नहीं थे। उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली Athlete गुलवीर सिंह ने ऐसे ही एक खेल में कमाल कर दिखाया है। उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले New York City Half Marathon में तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच डाला। वे एक घंटे से कम समय में Half Marathon पूरा करने वाले पहले भारतीय Athlete बने। Squash खिलाड़ी बेटी अनाहत सिंह ने Squash on Fire Open का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में

उन्होंने ये सफलता हासिल की। इसके साथ ही वे PSA World Ranking में Top-20 में जगह बनाने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मुझे अस्मिता Athletics League की जानकारी भी मिली है। इसमें 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर कई sporting events का शानदार आयोजन किया गया। League में करीब 02 लाख बेटियों ने भागीदारी की। ये देखकर अच्छा लगता है कि भारत की नारीशक्ति देश में हो रहे इस sporting transformation में अहम् भूमिका निभा रही है।

मेरा हमेशा से यह आग्रह रहा है कि आप सभी अपनी fitness पर जरूर ध्यान दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 100 दिनों से भी कम समय बचा है, पूरी दुनिया में योग के प्रति आकर्षण भी लगातार बढ़ रहा है। अफ्रीका के जिबूती में अल्मिस जी अपने अरविंद योग सेंटर के जरिए योग को बढ़ावा दे रहे हैं। वे यहां की कई और जगहों पर भी लोगों को योग सिखाते हैं। आपमें से कई लोगों ने Instagram Content Creator युवराज दुआ की post पर मेरे से reply को लेकर comments किए हैं। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं उनके पिता से कहूं कि वे sugar intake कम करें। मुझे खुशी है कि मेरे अनुरोध का उनके पिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी sugar intake को कम करें और जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमें खाने के तेल में 10 प्रतिशत की कटौती भी करनी है। इन छोटे-छोटे प्रयासों से आप मोटापे और lifestyle से जुड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे।

एक पुरानी कहावत है ‘करत करत अभ्यास के, जड़मत होत सुजान’ यानी हम जब निरंतर अभ्यास करते हैं तो उतनी ही ज्यादा बुद्धिमता हासिल करते जाते हैं। लोग भी सबसे बेहतर तब सीखते हैं जब उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। मुझे बेंगलुरु में शिक्षा से जुड़े एक unique प्रयास के बारे में जानकारी मिली है। यहां एक टीम Prayog Institute of Education Research चला रही है। इस टीम का Research Projects पर विशेष focus है। यह टीम school level पर science education को लोकप्रिय बनाने में जुटी है। उन्होंने ‘अन्वेषण’ नाम का एक प्रयोग किया है, इसके जरिए 9वीं से 12वीं class तक के students को Chemistry, Earth Science और Wellness जैसे क्षेत्रों में Innovation करने का मौका मिलता है - इससे Students को research का बहुत अच्छा अनुभव हासिल होता है साथ ही अपने Projects को publish करने का platform भी मिलता है।

परीक्षा पर चर्चा के दौरान कुछ Students ने मुझे बताया था कि वह science पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें इससे डर भी लगता है। इस दिशा में Prayog की टीम का प्रयास बहुत ही सराहनीय है, यह पहल, Students को science के साथ जुडने और Practically कुछ करके दिखाने का मौका देती है। जब हम किसी चीज को खुद करके देखते हैं - जिज्ञासा और रुचि पैदा होती है। कौन जानता है कि मेरे इन युवा साथियों में ही कोई आने वाले समय का बेहतरीन scientist हो।

शिक्षा के माध्यम से अतीत को संरक्षित करने और भविष्य को तैयार करने का एक प्रयास नागा समुदाय भी कर रहा है। इस समुदाय के लोग अपनी आदिवासी परंपराओं का बहुत सम्मान करते हैं। वो इस पर गर्व तो करते ही हैं साथ ही अपनी approach को आधुनिक भी रखते हैं। Naga tribes में मोरूंग लर्निंग की एक पारंपरिक व्यवस्था थी, इसमें बुजुर्ग लोग अपने अनुभवों से युवाओं को पारंपरिक ज्ञान, इतिहास और life skills के बारे में बताते थे। समय के साथ यह system अब मोरूंग concept of education में बदल गया है। इसके माध्यम से बच्चों में गणित और विज्ञान जैसे विषयों में रुचि पैदा की जाती है। इसमें समुदाय के बुजुर्ग उन्हें कहानियाँ, लोकगीत और पारंपरिक खेलों के साथ life skills सिखाते हैं। इस तरह हमारा नागालैंड अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए, बच्चों की शिक्षा को आगे ले जा रहा है। आपको भी अपने क्षेत्र में ऐसे प्रयासो के बारे में पता चले, तो मुझे जरूर share कीजिएगा।

देश के कई हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है यानि ये समय जल संरक्षण के अपने संकल्प को फिर से दोहराने का है। पिछले 11 वर्षों में ‘जल संचय अभियान’ ने लोगों को बहुत जागरूक बनाया है। इस अभियान के तहत देश-भर में करीब 50 लाख Artificial Water Harvesting Structure बनाए गए हैं। अब जल संकट से निपटने के लिए गाँव-गाँव में सामुदायिक स्तर पर प्रयास होने लगे हैं। कहीं पुराने तालाबों की सफाई हो रही है, कहीं बरसात के जल को सहेजने के लिए प्रयास किया जा रहा हैं। अमृत सरोवर अभियान के तहत भी देशभर में करीब 70 हजार अमृत सरोवर बनाए गए हैं। बारिश का मौसम आने से पहले इन सरोवरों की साफ-सफाई भी शुरू हो गई है। कुछ प्रेरक उदाहरण बताते हैं कि जनभागीदारी से जल संरक्षण का काम कितना व्यापक हो जाता है।

त्रिपुरा की जंपुई पहाड़ियों में बसा वांगमुन गाँव 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। ये गाँव पानी के गंभीर संकट का सामना कर रहा था। गर्मियों के दिनों में गाँव के लोग पानी के लिए लंबी दूरी तय करते थे। आखिरकार गाँव के लोगों ने बारिश की हर बूंद को सहेजने का निर्णय किया। आज वांगमुन गाँव के लगभग हर घर में Rooftop Rainwater Harvesting System स्थापित हो गया है। जो गाँव कभी पानी की कमी से जूझ रहा था, वो जल संरक्षण की एक प्रेरक मिसाल बन गया है।

इसी तरह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी एक अनोखी पहल देखने को मिली। यहां के किसानों ने एक सरल लेकिन प्रभावशाली idea पर काम किया। यहां के किसानों ने अपने खेतों में छोटे-छोटे recharge तालाब और सोखता गड्ढे बनाएँ जिससे बारिश का पानी खेतों में ही रुकने लगा और धीरे-धीरे वह जमीन के अंदर जाने लगा। आज इस क्षेत्र के 1200 से अधिक किसान इस model को अपना चुके हैं और गाँव का ground water level बहुत बेहतर हो गया है। इसी तरह तेलंगाना के मंचेरियाल जिले के मुधिगुंटा गाँव में भी लोगों ने मिलकर पानी की समस्या दूर की है। गाँव के 400 परिवारों ने अपने घरों में soak pit बनाया और water conservation का जन-आंदोलन बना दिया। इससे गाँव का ground water level बेहतर हुआ है, साथ ही प्रदूषित पानी की वजह से होने वाली बीमारियाँ बहुत कम हो गई हैं।

हमारे मछुआरे भाई-बहन सिर्फ समुद्र के योद्धा नहीं हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत नींव भी हैं। वे सुबह होने से पहले समन्दर की लहरों से जूझते हुए, अपने परिवार

के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में जुट जाते हैं। ऐसे मेहनतकश मछुआरों का जीवन आज कई तरह से आसान बनाया जा रहा है। चाहे बंदरगाहों का विकास हो या मछुआरों के लिए बीमा, ऐसी कई पहल उनके बहुत काम आ रही है। हम जानते हैं कि समन्दर में उनकी गतिविधियों को मौसम का रुख बहुत प्रभावित करता है। इसे देखते हुए Technology के जरिए भी उनकी पूरी मदद की जा रही है। मुझे बेहद खुशी है कि ऐसे प्रयासों से हमारा fisheries sector न केवल समृद्ध हो रहा है, बल्कि कुछ नया करने का जज्बा भी भर रहा है। आज fisheries और seaweed के क्षेत्र में नए-नए innovation हो रहे हैं, और हमारे मछुआरे भाई-बहन आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ओडिशा के सम्बलपुर की सुजाता भूयान जी एक गृहणी थीं, लेकिन वो कुछ नया करके अपने परिवार की और मदद करना चाहती थी। इसलिए कुछ वर्ष पहले उन्होंने हीराकुंड reservoir में Fish-Farming शुरू की। शुरुआती दिन उनके लिए आसान नहीं थे। मौसम में होने वाले बदलाव, मछलियों के खाने का प्रबंध और घर की जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाने जैसी कई चुनौतियाँ थीं, लेकिन उनका हौसला अडिग था। केवल दो-तीन वर्ष के भीतर उन्होंने अपने प्रयास को एक फलते-फूलते business में बदल दिया। आज उनकी सफलता समुदाय की महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बन गई।

लक्षद्वीप में मिनीकॉय के हाव्वा गुलजार जी की कहानी हमारी माताओं-बहनों की अद्भुत संकल्प-शक्ति को सामने लाती है। दरअसल वे एक Fish Processing Unit चलाती थीं। लेकिन उन्हें लगा कि उनके पास एक अच्छा Cold Storage हो तो वे और बेहतर कर सकती हैं, इसलिए, उन्होंने Cold Storage Unit लगाने का फैसला किया। आज यही उनकी ताकत बन चुका है। अब वे बेहतर Planning के साथ कारोबार कर पा रही हैं।

देश में आज हर तरफ ऐसे प्रयास हो रहे हैं, जो प्रेरित करने वाले हैं। बेलगावी के शिवलिंग सतप्पा हुद्दार ने पारंपरिक खेती से अलग रास्ता चुना। इसके लिए उन्होंने एक Pond Farm बनाया। इस कारोबार के लिए उन्हें training भी मिली। अब अपने Pond से मछलियों की बिक्री कर वे अच्छी कमाई कर रहे हैं। वहीं Seaweed की मांग को देखते हुए कई लोगों ने Seaweed Cultivation को भी अपनाया है। इसका उन्हें बड़ा लाभ भी हो रहा है। मैं एक बार फिर Fisheries Sector से जुड़े सभी लोगों की सराहना करता हूं। हमारी Economy को सशक्त बनाने के लिए उनका प्रयास बेहद प्रशंसनीय हैं।

जब समाज खुद आगे आता है, तो छोटे-छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव की नींव बन जाते हैं। हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं, जो हमें यही सिखाते है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक प्रेरक प्रयास देखने को मिला। वहाँ एक ही घंटे में 2 लाख 51 हजार से अधिक पौधे लगाए गए और एक नया Guinness World Record बना। इस प्रयास की सबसे खास बात ये रही कि इसमें हजारों लोग एक साथ जुड़े। छात्र, जवान, स्वयंसेवी संगठन, अलग-अलग संस्थाएं, सबने मिलकर इस काम को संभव बनाया। जनभागीदारी का यही स्वरूप 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के दौरान भी दिखता है। इस अभियान के तहत देशभर में करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं।

नागालैंड के चिजामी गाँव से भी एक बहुत प्रेरक प्रयास सामने आया है। चिजामी गाँव की महिलाएं मिलकर 150 से अधिक variety के पारंपरिक बीजों को सुरक्षित रख रही हैं। इन बीजों को एक community seed bank में संरक्षित किया जा रहा है, जिसे गाँव की महिलाएं ही चलाती हैं। इनमें चावल, बाजरा, मक्का, दालें, सब्जियाँ और कई तरह की जड़ी-बूटियाँ शामिल हैं। यह एक ऐसा प्रयास है, जिसमें ज्ञान भी सुरक्षित है, परंपरा भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों के लिये एक मजबूत आधार भी तैयार हो रहा है।

आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब ऐसे प्रयास हमें यह बताते हैं कि समाधान हमेशा कहीं दूर नहीं होता। कई बार हमारे अपने पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रयास ही हमें सबसे मजबूत रास्ता दिखाते हैं।

आज आप देश के किसी छोटे-बड़े शहर में जाएंगे तो एक बदलाव आप जरूर notice करेंगे। आपको बड़ी संख्या में घरों की छत पर solar panel लगे हुए दिखाई देंगे। कुछ साल पहले तक ये इक्का-दुक्का घरों पर ही दिखता था। लेकिन आज 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' का प्रभाव देश के कोने-कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुंजपारा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से solar power technology की training ली और 4 महीने का Solar PV technician का course पूरा किया। अब वो एक कुशल solar technician बन गई हैं। पायल एक सोलर उद्यमी के तौर पर अपनी पहचान बना रही हैं। वो आस-पास के जिलों में solar rooftop installation का काम करती हैं और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।

मेरठ के अरुण कुमार भी अब अपने

इलाके में ऊर्जा दाता बन गए हैं। हाल ही में, दिल्ली में हुए कार्यक्रम में अरुण कुमार ने हिस्सा लिया था और अपने अनुभव साझा किये थे। उन्होंने बताया था कि वो न केवल बिजली बिल की बचत कर रहे हैं, बल्कि अपनी अतिरिक्त बिजली बेच भी रहे हैं।

जयपुर के मुरलीधर जी की सफलता भी कुछ ऐसी ही है। पहले उनकी खेती डीजल पंप पर निर्भर थी, जिसमें हर साल हजारों रुपए खर्च होते थे। जब उन्होंने solar pump अपनाया, तो उनकी खेती का तरीका ही बदल गया। अब उन्हें ईंधन की चिंता नहीं रहती, सिंचाई समय पर होती है, और उनकी सालाना आय भी बढ़ गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब उनका परिवार साफ ऊर्जा के साथ, बेहतर जीवन जी रहा है।

‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ का फायदा North East के इलाकों में भी मिल रहा है। त्रिपुरा में रियांग जनजाति के कई गाँव ऐसे थे, जहाँ बिजली की समस्या थी। अब solar mini-grid के माध्यम से वहाँ के घरों में रोशनी रहती है। वहाँ बच्चे अब शाम के बाद भी पढ़ पा रहे हैं। लोग mobile charge कर पा रहे हैं और गाँव का सामाजिक जीवन भी बदल गया है।

देश में solar ऊर्जा क्रांति के ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। आप भी इस क्रांति से जुड़िये और दूसरों को भी जोड़िये।

‘मन की बात’ के लिए मुझे हर महीने देश के अलग-अलग हिस्सों से ढेरों संदेश मिलते हैं। इन संदेशों से ये भी पता चलता है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में बैठे लोग कितने चाव से इस कार्यक्रम को सुनते हैं। जब मैं आपके सुझाव पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, ये हम सबका एक साझा संवाद बन गया है। आपके विचार, आपके अनुभव, इस कार्यक्रम को लगातार बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। आप अपने आसपास की प्रेरक गाथाएं यूं ही साझा करते रहिए। हो सकता है, आपकी एक छोटी सी कोशिश, किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ले आए, किसी को आगे बढ़ने का नया हौसला दे दे - यही तो रेडियो की असली ताकत है। ये देश के अलग-अलग कोने में बैठे लोगों का एक विचार, एक भावना और एक उद्देश्य जोड़ देता है। ■

‘मन की बात’ प्रेरणादायक है - नितिन नवीन

असामान्य वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद देश आज मजबूत स्थिति में है तो यह केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व के बल पर ही है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जनप्रिय कार्यक्रम ‘मन की बात’ से विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद स्थापित होता है और समाज से जुड़े व्यक्तिगत प्रयासों को एक राष्ट्रीय मंच मिलता है। असामान्य वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद देश आज मजबूत स्थिति में है तो यह केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व के बल पर ही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है और देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं होने दी जाएगी।

‘मन की बात’ केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसा गैर-राजनीतिक मंच है जिसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश भर के आम नागरिकों की प्रेरणादायक कहानियों और उनके सामाजिक योगदान को देशवासियों तक पहुंचाते हैं। इस मंच के जरिए समाज के अलग-अलग वर्गों द्वारा किए जा रहे व्यक्तिगत प्रयासों, नवाचारों और सेवा कार्यों को एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं और देश में जनभागीदारी की भावना को बल मिलता है। यह कार्यक्रम समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणा का स्रोत है और प्रत्येक नागरिक को इसे अवश्य सुनना चाहिए। ■

समाज को सकारात्मक संदेश
- डॉ. मोहन यादव

‘मन की बात’ के जरिए देश की छिपी प्रतिभाएं जनता के सामने आ रही हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देशभर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रेरक प्रसंगों के जरिए छिपी हुई प्रतिभाओं को जनता के सामने लाने का कार्य कर रहे हैं। ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुनकर हम सभी प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में उतारकर आगे भी बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ‘मन की बात’ में गैर राजनीतिक विषयों को लाकर समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। हर क्षेत्र में लगातार विकास किया जा रहा है। इंदौर एयरपोर्ट में टर्मिनल-एक का उद्घाटन किया गया। इस सौगात से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ देश-विदेश के आने वाले मेहमानों, व्यवसायियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश को सभी क्षेत्रों में विकसित बनाने के साथ आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। ‘मन की बात’ कार्यक्रम से लोग प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। आने वाले दिनों में मध्यप्रदेश विकास और प्रगति के मामले में नए आयाम स्थापित करेगा। ▪

आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली
- हेमंत खण्डेलवाल

प्रधानमंत्री जी हर वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहें हैं पेट्रोल-डीजल व गैस का पर्याप्त स्टॉक है, अफवाहों से बचें व अनावश्यक स्टोर न करें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देशभर के अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों व संस्थाओं की सफलता की कहानी देश की जनता के सामने लाकर लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को प्रतिपादित करते हुए देश के विकास में उनके योगदान की बात की है। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर देश के विकास में उनके योगदान पर भी बात की है। प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को फिटनेस बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, अमृत तालाब योजना में मछली पालन करने, कोल्ड स्टोरेज के जरिए लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करने और अपनी आय बढ़ाने के कई मंत्र दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की ‘मन की बात’ कार्यक्रम को देश-प्रदेश के हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, इससे स्वयं नई-नई जानकारी मिलती है, जिससे प्रेरणा लेकर लोग खुद की आय बढ़ाने के साथ देश और समाज को और मजबूती देने में अपना योगदान दे सकते हैं।

ईरान, अमेरिका व इजराइल के युद्ध से पूरी दुनिया की पेट्रोलियम आपूर्ति पर संकट आया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर कई देशों से संवाद किया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार कई बार स्पष्ट कर चुकी हैं कि मध्यप्रदेश और देश में पेट्रोल-डीजल, गैस का पर्याप्त स्टॉक है। परेशान न हों, अनावश्यक रूप से पेट्रोल-डीजल व घरेलू गैस का स्टोर न करें। प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल-डीजल के दाम देश में नहीं बढ़ने दिए। हर नागरिक को सरकार का सहयोग करना चाहिए और अफवाहों से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं आने वाली है, इसलिए निश्चिंत रहें। ▪

बजट भविष्य के भारत की आधार शिला

योगेन्द्र नाथ बरतरिया

मोदी सरकार में देश का बजट 2014 के 17.95 लाख करोड़ रुपये से प्रारम्भ होकर 2026-2027 में लगभग तीन गुना होकर 53.47 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। **अर्थात, लगभग 13 वर्षो के शासन काल में देश का बजट लगभग 3 गुणा हो गया, यह शानदार, अविश्वसनीय और अभूतपूर्व उपलब्धि है मोदी सरकार की।**

यूं तो मोदी सरकार का बजट प्रस्ताव सरकार के कार्यक्रम, नीतियां, उद्देश्य, जनता से किया गया वादा निभाने का एक दस्तावेज होता है। इसमें देश के वर्तमान व भविष्य की आशा और आकांक्षाएं छुपी होती हैं। मोदी सरकार 2014 से लगातार देश का बजट बना रही है। बजट प्रधानमंत्री जी के विचार, नीतियां, भविष्य की अपेक्षाएं या प्रधानमंत्री जी देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं यह दिखाती हैं। भारत शनैः शनैः 11 वीं अर्थव्यवस्था से पांचवी अर्थव्यवस्था तक का मार्ग पार कर गया और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहा है। जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मोदी सरकार का यह बजट 2014 से आज तक के तैयार ग्राउंड के ऊपर वर्तमान के साथ भविष्य की तरफ बढ़ने का रास्ता है। यूं तो कहा जाए भारत की आज तक की आर्थिक गतिविधि एवं विस्तार या आधार जो विभिन्न सरकारों द्वारा तैयार किया गया था, जो श्री नरेंद्र मोदी जी को विरासत के रूप में मिला था। पुरानी सरकारों की इस विरासत को सजाने, संवारने और सुरक्षित एवं विकसित रूप में भविष्य की पीढ़ी को देने का जो दायित्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है या श्री नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर है, उसे निभाने का श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट में क्षमताओं, अनुभव व दूरदर्शिता से भरा हुआ प्रयास किया है। मोदी सरकार को 2014 में विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला था, नभ, जल, थल में भ्रष्टाचार और घोटालों की गूंज सुनाई पड़ती थी। युवा शक्ति निराशा के भाव में थी। युवा परेशान था। व्यापार व्यवसाय निम्न स्तर पर थे। निवेश की कोई कल्पना नहीं थी। विदेशी निवेश भारत का रास्ता भूल चुका था। किसान हैरान था। महिलाओं के पास कोई अवसर भी नहीं थे या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो युवा, किसान, महिला, गरीब के पास बहुत सीमित संसाधन थे। एक वर्ग था जो काफी ऊपर था और दूसरा वर्ग था जो गरीबी की रेखा के नीचे था और जो मध्यम वर्ग था वह ना तो खुल के सांस ले पा रहा था ना चैन की नींद सो पा रहा था। अपनी रोटी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मोदी जी ने 2014 में निराशा के दौर में सरकार संभाली। सरकार संभालने को राजनीतिक परिवर्तन कहना बहुत छोटे शब्दों में विश्लेषण करना होगा। सरकार के दायित्व असीमित होते हैं जो इस बात को माने, जो सरकार सत्ता को उपभोग का साधन मानती है उसके लिए दायित्व की चर्चा करना व्यर्थ है। जो सरकार सत्ता को सेवा का माध्यम मानती

वित्तीय वर्ष 2026-2027 का केन्द्रीय बजट भारत की महिला वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत 9 वां बजट, भारत की नारी शक्ति के सशक्त होने का स्पष्ट प्रतिबिंब है।

है उस सरकार के लिए दायित्व का बोध उसे चैन की नींद सोने नहीं देगा। उस सरकार के सामने 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी कंधे पर होती है। 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विश्व के बदलते दौर में अपने आप को साबित करने के योग्य बनाना, रोजगार व्यवस्था करना तथा सम्मान जनक जीवन प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोदी सरकार ने धीरे-धीरे किसानों को कर्जों के जाल से बाहर निकाला, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज की व्यवस्था की, दो वक्त की चैन की रोटी की गारंटी दी,9.35 करोड़ मुफ्त इलाज की व्यवस्था नागरिकों को दी, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला कर रोजगार की व्यवस्था की, प्रधानमंत्री ने विश्व की सभी सरकारों से संबंध स्थापित करके भारत के संबंधों में सुधार किया, अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, यातायात के साधन सुधारे, महिलाओं को नीति-निर्णय में भागीदारी दी, नीतिगत निर्णय के साथ- साथ शासन एवं देश की व्यवस्था में बराबरी का हक दिया, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया, एक तरीके से देखा जाए तो मोदी जी ने देश की 50 प्रतिशत आबादी जो अभी देश के विकास में अपना कॉन्ट्रिब्यूशन देने के लिए जो तत्पर थी और घर पर बैठी थी, उसको घर से बाहर निकाल कर देश की मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में सहयोगी बनाया, महिलाओं को भारत के विकास में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का मौका दिया या यूँ कहें कि मोदी जी ने देश के समस्त नागरिकों को,140 करोड़ लोगों को देश के विकास में सहभागी बनाया।

देश का विकास अकेले मोदी जी नहीं कर सकते, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के विकास में 140 करोड़ लोगों का सहयोग चाहिए, 140 करोड़ लोगों की सहभागिता चाहिए, सहभागिता और सहयोग के बाद विकास भी 140 करोड़ लोगों का ही होगा, सरकार यह बात स्पष्ट रूप से जानती थी, सरकार ने पुरानी परंपराओं को तोड़ा, पुरानी सरकार बनाने की नीतियों को छोड़ा, नया दृष्टिकोण देश के सामने प्रस्तुत किया, इस दृष्टिकोण में सरकार ने सिद्धांत के रूप से मान लिया था कि देश का विकास तभी संभव है, जब देश के 140 करोड़ लोगों की इसमें सहभागिता होगी, अब सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्लेटफार्म बनाना शुरू किया, इस कार्यक्रम में या इस उद्देश्य की प्राप्ति में बाधाएं भी बहुत थीं, पुरानी सरकारों के अपने अनुभव, अपनी सरकार बनाने के लिए योजनाएं, उद्देश्य, अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए योजनाएं, इस तरीके से बहुत सारे पहलू होते हैं जो सरकार की दिशा को तैयार करते हैं या सरकार की नीतियों को तैयार करते हैं, मोदी जी ने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया, सरकार की दिशा, सरकार की दशा और सरकार की वापस सरकार बनाने की अनुकूलता इन विषयों को जनता के ऊपर छोड़ा और 140 करोड़ लोगों को मोदी जी ने कहा यह मेरा परिवार है और 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर ध्यान केंद्रित किया और जब 140 करोड़ लोगों को देश का प्रधानमंत्री अपना परिवार मानकर ध्यान केंद्रित करेगा तो कोई भी उसके सामने व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई भी व्यक्ति उससे दूर नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसके बहुत नजदीक नहीं है, शरीर का कोई भी हिस्सा शरीर के लिए उतना ही बराबर है, जितना कोई दूसरा हिस्सा, विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं भी धीरे-धीरे खत्म करीं, कश्मीर से 370 का नमस्ते, तीन तलाक को नमस्ते, कई करों के मकड़ जाल को नमस्ते, फर्जी नोटों की समस्या को नमस्ते, त्वरित भुगतान सुविधा को सुनिश्चित किया, तकनीक से जोड़ा, भुगतान में होने वाले भ्रष्टाचार पर नकेल कसी, सीमा पार आतंकवाद रोक कर सीमाओं को सुरक्षित बनाया, देश के नागरिकों में भविष्य के प्रति उत्साहवर्धन किया, सेना को मजबूत बनाया, सेना का आधुनिकीकरण किया, आयात में होने वाले व्यय को कम से कम करना, महिलाओं को भारत के विकास में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का मौका दिया या यूं कहे कि मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को देश के विकास में सहभागी बनाया तो आप मोदी जी के बजट को बहुत नजदीक से समझ पायेंगे।

आप यह भी कह सकते हैं कि इन चर्चाओं का बजट विश्लेषण से क्या लेना-देना? यह तो सब राजनीतिक निर्णय थे? जो मोदी जी ने समय के हिसाब से तथा अपने दल के सिद्धांतों के हिसाब से निर्णय लिए, यहीं तो चूक हो जाती है, यह केवल राजनीतिक निर्णय नहीं थे, यही वह निर्णय थे जिनसे देश के भविष्य के आधार का प्लेटफार्म तैयार हुआ, देश के भविष्य के लिए रास्ता निकाला, इसको आप दूसरे शब्दों में कहें - पेड़ पर फल तब लगता हैं- जब पेड़ के लिए जमीन तैयार की जाती है, पेड़ के पौधारोपण के साथ-साथ उसके लिए खाद, पानी और जानवरों से सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, फिर पेड़ पर फल आता है, इसी सिद्धांत के ऊपर देश की आर्थिक व्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। मोदी जी ने विरासत में मिले ढांचे के साथ-साथ भविष्य की आशाओं, अपेक्षाओं एवं भविष्य के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए ढांचे में सुधार किया, नया ढांचा बनाया, ढांचे को मजबूत किया, ढांचे को लीक प्रूफ बनाया, ढांचे में वह व्यवस्था जमाई जिसमें तेजी से दौड़ने के लिए, देश को नए रास्ते पर ले जाने के लिए, देश को दौड़ में शामिल होने लायक बनाया। आज देश की सफलता केवल बजट में फंड के बंटवारे से नहीं मिलने वाली, देश को फंड के बंटवारे के बाद दिशा चाहिए, आधार चाहिए, देश को ढांचा चाहिए, देश को विकास का प्लानिंग चाहिए, प्लान चाहिए, मोदी जी ने इन सब चीजों को समझा, देश के सामने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा, आप

INCOME TAX
FINANCE

कह सकते हैं दूरदृष्टि का ही परिणाम होगा जिससे विकसित भारत@ 2047 का मंत्र सिद्ध होगा।

अब आप आए बजट के फंड वितरण के ऊपर या बजट एलोकेशन के ऊपर बजट को देखें - मोदी जी ने इस बजट में ऐसी कोई भी घोषणा नहीं करी जो लोक लुभावन कहलाती हो, लोक लुभावन किसी भी योजना में फंड खर्च करने से मोदी जी ने परहेज किया है, मोदी जी ने बजट में विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को साधने का प्रयास किया है।

अब आप फिर एक बात याद रखिये विकसित भारत@2047 एक पड़ाव मात्र है, भारत की राजनीति का, भारत के आर्थिक विकास का, भारत के आर्थिक भविष्य का, एक पड़ाव मात्र है 2047 का भारत, 2047 का भारत अगले भारत के लिए लक्ष्य, मंत्र तैयार करेगा, विकसित राष्ट्र की दिशा में भारत सुधार की रफ्तार तेज करेगा, बजट में इस रफ्तार को ऊर्जा और गति दी है, बजट में युवाओं को संभावनाएं प्रदान की हैं, बजट में राजकोषीय घाटे को कम करके, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।

विकास दर को बनाए रखने का प्रयास किया है। बजट पूर्व भारत सरकार ने कई देशों के साथ व्यापार समझौतों को अंजाम दिया है। जिनका उद्देश्य भारत के औद्योगिक विकास दर को बढ़ाना था। औद्योगिक विकास दर के बढ़ने के पीछे का जो उद्देश्य है वह युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना था। मोदी सरकार ने वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने को दृष्टिगत रखते हुए बजट में बायो फार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र, वस्त्र उद्योग, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों को बजट में महत्वपूर्ण स्थान देकर अपना समर्थन दिया है। सरकार का समर्थन इन क्षेत्रों के विकास के लिए नए रास्ते खोलेगा। इन क्षेत्रों के विकास के पीछे की अगर कहानी देखी जाए या इन क्षेत्रों के विकास से प्राप्त होने वाली वास्तविक क्षमता को देखा जाए तो एक तरफ तो देश इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करता है, दूसरी तरफ इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर भारत युवाओं को अवसर प्रदान करता है अर्थात् युवाओं को अवसर प्रदान करके भारत आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता है और युवाओं को अवसर प्रदान करने का अर्थ युवाओं के लिए रोजगार के नए क्षेत्रों को खोलना। यही मोदी जी की दूरदर्शिता है, जिसके परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके परिणाम भविष्य के भारत में, भारत के निर्माण में दिखाई देंगे। मोदी जी को मालूम है व्यापार-व्यवसाय को समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचे पर मजबूत प्रयास की आवश्यकता है। जब तक बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगा, व्यापार व्यवसाय मजबूत नहीं हो सकता, इस समस्या को समझ कर मोदी सरकार ने देश भर में जलमार्गों के विस्तार की योजना बनाई, माल ढुलाई की योजना बनाई, हाई-स्पीड रेल चलाने की योजना बनाई, यह निर्णय देश के आर्थिक विकास की आधार शिला सिद्ध होगा, स्वास्थ्य-मोदी सरकार की प्राथमिकता में रहा है, यह मोदी सरकार ही है जिसने आयुष्मान कार्ड के द्वारा नागरिकों को स्वास्थ्य के लिए होने वाले खर्चों से मुक्त किया, मेडिकल कॉलेजों को देश के कोने- कोने में खोला, नर्सिंग कॉलेजों को देश के कोने-कोने में खोला, एम्स कॉलेजों को देश के कोने-कोने में खोला, स्वास्थ्य क्षेत्र में किया गया परिवर्तन अभूतपूर्व है, स्वास्थ्य सुविधा के लिए किया गया परिवर्तन अभूतपूर्व है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया ढांचागत परिवर्तन वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करेगा ही, देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा ही, स्वस्थ नागरिक ही देश की उन्नति में सहयोग कर सकता है और स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो देश का आर्थिक स्वास्थ्य भी अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। स्वास्थ्य में सरकार का फोकस निश्चित रूप से आवश्यक भी था और सराहनीय भी है। इस बार बजट में मोदी सरकार ने नए चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना, स्वास्थ्य से संबंधित पेशेवरों की भर्ती की बात कही है। एक तरफ तो रोजगार बढ़ेगा, दूसरी तरफ भविष्य के रोजगारों को बचाने के लिए या भविष्य के रोजगारों को चलाने के लिए स्वास्थ्य का सहयोग प्रदान करेगा, मोदी सरकार का यह निर्णय दूरगामी परिणाम लेकर आएगा।

बजट में प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए नए छात्रावासों के निर्माण का कार्यक्रम प्रस्तावित है, छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण, देश भर में उन छात्राओं के लिए विशेष सहायक सिद्ध होगा जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहकर के शहर में शिक्षा प्राप्त कर अपना भविष्य संवारना चाहती हैं। ध्यान रखिए छात्र या छात्राओं का भविष्य संवारने में सरकार का किया गया सहयोग देश का भविष्य संवारने के कार्यक्रम का एक हिस्सा होता है, और छात्र या छात्राओं का भविष्य सुधारने का कार्यक्रम देश के भविष्य को सुधारने में सरकार का अत्यावश्यक, महत्वपूर्ण एवं दूरदर्शिता पूर्ण कदम सिद्ध होगा।

सरकार ने मत्स्य पालन और पशुपालन में उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया है, गांव के युवाओं को गांव में रोजगार प्रदान करने में या किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सरकार का यह कदम सहायक सिद्ध होगा।

बजट का राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो मोदी सरकार ने किसी विशेष क्षेत्र को, किसी विशेष समाज को, किसी विशेष समुदाय को साधने की जगह 140 करोड़ लोगों को भविष्य प्रदान करते हुए 140 करोड़ लोगों को साधने का प्रयास किया है। किसी सरकार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने बजट के माध्यम से किन-किन को किस-किस तरह से साधती है, मोदी जी ने लेकिन फिर सिद्ध किया कि वह 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उन्होंने बजट के माध्यम से 140 करोड़ लोगों को साधने का प्रयास किया है, इसलिए मोदी जी और उनकी टीम को बधाई मिलना चाहिए। यह देश के लिए समर्पित बजट है देश के भविष्य के लिए समर्पित बजट है। ■

(लेखक चरैवेति पत्रिका के कार्यकारी सम्पादक हैं)

कट्टर देशभक्त डॉ. भीमराव अम्बेडकर

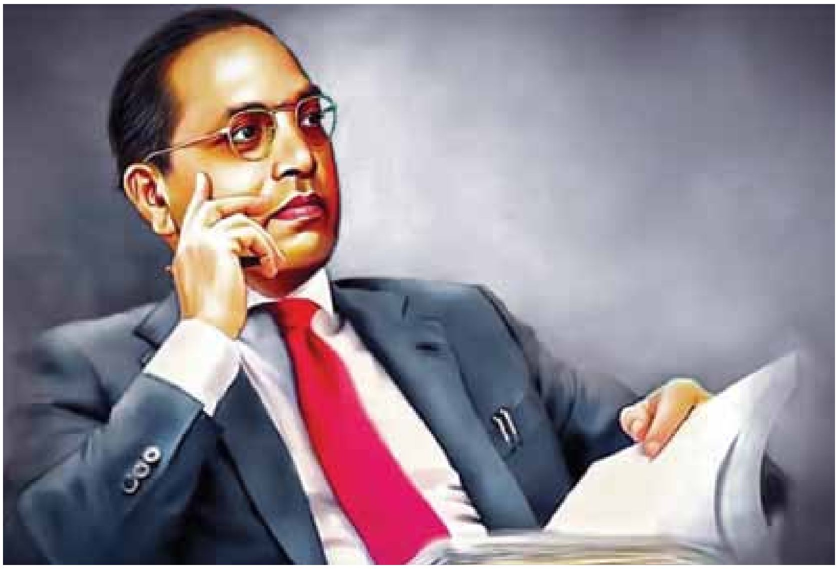

अपने समाज में भी मानवीय स्वभावों की प्रक्रियानुसार कुछ लोगों ने स्वयं ही जन्मजात बड़प्पन धारण किया था। अतः वे पिछड़े, अविकसित, निर्धन लोगों को निम्न या छोटे समझना अपना अधिकार मानते थे। ऐसे पाखंडी तथाकथित समाज-धुरीणों की बाबासाहेब ने बहुत ही कड़े शब्दों में आलोचना की तथा उनके तर्कों का जोरदार खंडन किया। उनकी इस आलोचना का स्तर देखकर ही उनकी कट्टर देशभक्ति तथा विद्वता का परिचय मिलता है। इस दृष्टि से संविधान-सभा में 5 फरवरी 1950 को दिया गया उनका महत्वपूर्ण भाषण अध्ययन एवं मनन योग्य हैं। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था कि 'भारत शताब्दियों बाद स्वाधीन हुआ है। हम केवल 150 वर्ष गुलाम थे- पं. नेहरू की यह मान्यता उन्हें पूर्ण रूप से अस्वीकार थीं। अब इस स्वराज्य की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य हैं।

अपने समाज में किसी प्रकार की फूट पुनः हमसे स्वराज्य को छीन लेगी। शताब्दियों की गुलामी के परिणामस्वरूप हममें कुछ विकृतियाँ, उच्च-नीच भेद, आर्थिक विषमता, पिछड़ापन, जातिवाद आदि उत्पन्न हुए हो सकते हैं, परन्तु इसे अपना हथियार बनाकर कोई विदेशी हमारे स्वत्वों का अपहरण करना चाहेंगे तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। हम उनकी यह आकांक्षा मिट्टी में मिला देंगे। यह हमारा घरेलू मामला है, इसलिए हम इससे आपस में निबटेंगे। अपने लाभ मात्र या सामाजिक दृष्टि से अनवट स्थिति से निकलने की इच्छा से हम किसी विदेशी के हस्तक नहीं बनेंगे। हमें अपने में उत्पन्न होने वाले जयचंदों से सावधान रहना होगा। अपने जिस राष्ट्र एवं समाज के हम अंग-उपांग हैं, उसके हित को ठीक प्रकार से पहचानें।'

दो महापुरूष-दो दृष्टिकोण

पथभ्रष्ट अहंकारारूढ़ सवर्ण हिन्दू बंधुओं का हृदय-परिवर्तन करने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। उन दिनों यही काम एक और भी महापुरूष अपने विशेष ढंग से कर रहे थे। वे थे पूज्य महात्मा गांधी। उनकी प्रामाणिकता, निष्ठा, असीम प्रयत्नशीलता तो उनके विरोधियों में भी शंका से परे थी। उन्होंने भी शब्द का नव मूल्यांकन करने के लिए स्वयं को भंगी बताना, उन्हीं के मुहल्ले-मकानों में ठहरना, खाना-पीना प्रारंभ किया।

समाज के नामसझ स्वयंभू नेताओं ने जिन्हें अस्पृश्य कहा था, महात्मा जी ने उन्हें हरिजन कहा। यद्यपि भड़काने वाले अनेक निहित स्वार्थी नेता विद्यमान थे, फिर भी इन दोनों महापुरूषों के प्रयत्नों के फलस्वरूप यह दलित-पीड़ित वर्ग विक्षुब्ध होते हुए भी अपनी सामाजिक, आर्थिक, उन्नति के लिए ही प्रयत्नशील रहा। साथ ही इन महापुरूषों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही अपना विवेक न खोते हुए उसने अत्याचार सहे, पर अपने हिन्दू समाज के प्रति आत्मीयता में कमी न आने दी। वैसे यह बात अलग है कि इन दोनों के विचार पूरी तरह आपस में न मिलते हों। डॉ. अम्बेडकर 'हरिजन' शब्द-प्रयोग के विरूद्ध थे। महात्मा जी की सदाशयता को स्वीकार करने के बाद भी वे अनुभव करते थे कि हरिजन नाम देने के लिए सवर्ण अपने को सदैव उपकारकर्ता ही मानते रहेंगे। अतः परस्पर भेद तथा उच्च-नीचता की बात तो बनी ही रही।

भारत शताब्दियों बाद स्वाधीन हुआ है। हम केवल 150 वर्ष गुलाम थे- पं. नेहरू की यह मान्यता उन्हें पूर्ण रूप से अस्वीकार थीं। अब इस स्वराज्य की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य हैं।

यह स्थिति अत्यंत अपमानजनक है, ऐसा वे मानते थे। अतः उन्हें इस हरिजन नामाभिधान से अत्यंत चिढ़ थी। महात्मा गांधी और डॉ. अम्बेडकर दोनों के प्रयत्नों का लक्ष्य समान होने पर भी भूमिका एवं प्रक्रिया (Approach) भिन्न थी। दोनों महान थे। परन्तु एक का प्रयास बाहर से था तो दूसरा स्वयं भुक्तभोगी होने के कारण स्वानुभव से उत्पन्न कसक से मर्माहत होकर प्रयत्नरत था। इतना होने पर भी श्रद्धेय बाबा साहेब प्रतिक्रिया की भावना से सर्वथा अलिप्त थे। महात्मा जी का प्रयास मानवीय भावना से प्रेरित था। जैसे अमेरिका में नीग्रो लोगों के उद्धार के लिए किये जाने वाले प्रयासों में लिंकन का स्थान था, उसी प्रकार भारत में अस्पृश्योद्धार के प्रयासों में महात्मा जी का था। परन्तु डॉ. अम्बेडकर का प्रयास बुकर टी वाशिंगटन, मार्टिन लूथरकिंग के समान था। महानता में समान होने पर भी दोनों की भूमिका में उनकी स्वयं की भिन्न स्थिति के कारण अंतर था-वैसे ही भारत में भी दोनों की भावनाओं को मिले शब्दों के रूप में भिन्नता होने पर भी उनकी अपने समाज के प्रति समान आत्मीयता थी। ▪

शिवाजी ने कहा मेरा नहीं धर्म का राज्याभिषेक है

माओ और चे-ग्वेबेरा से लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व शिवाजी ने गुरिल्ला युद्धतंत्र का निर्माण किया। नेपोलियन और हिटलर के मास्को अभियान के अनुभवों के सैकड़ों वर्ष पहले, युद्ध के दौरान संभाव्य आपातकाल में आश्रय स्थान के नाते, सुदूर दक्षिण में उपयुक्त प्रदेश सम्पादित करने की दूरदर्शिता उन्होंने दिखायी।

शास्त्र के नाते 'जिओपोलिटिक्स' का विकास होने के 250 वर्ष पूर्व उन्होंने सागरीय सत्ता का सूत्रपात प्रयास पूर्वक किया।

19 फरवरी सन् 1630, नवीन मत 16 अप्रैल 1627 प्राचीन मत की कोख से ज्योति-श्लाका का प्रस्फुटन वह भाग्यशाली दिन, जिसने इतिहास के एक अद्वितीय व्यक्तित्व शिवाजी को इस धर्मभूमि पर अवतीर्ण किया-शून्य से सृष्टि का निर्माण करने वाले कर्तृत्व के सूत्रपात का पावन दिवस।

संसार के गुण-सम्पन्न अनेकानेक महापुरूषों की शिवाजी से तुलना की जा सकती हैः सेना संचालन की दृष्टि से सिकन्दर, सीजर, हानिबाल और नेपोलियन दारूण निराशा की घड़ियों में जनता का मनोधैर्य टिकाए रखने की क्षमता की दृष्टि से लिंकन और चर्चिल, प्रखर राष्ट्रभाव को जागृत और संगठित करने में मैजिनी, वाशिंगटन तथा बिस्मार्क, राष्ट्र-निर्माण-कार्य में आत्मविसर्जन की दृष्टि से कमालपाशा और लेनिन, आसक्ति रहित शासन करने मे मार्क्स आरेलियस तथा चार्ल्स पंचम। किन्तु सम्पूर्ण गुण समुच्चय की दृष्टि से शिवाजी की तुलना किससे करें? कल्याण के सूबेदार की लावण्यमयी पुत्रवधू को मातृवत् सम्मानित करने वाले छत्रपति के चरित्र की तुलना हम अन्य किस सत्ताधीश से करें?

माओ और चे-ग्वेबेरा से लगभग तीन सौ वर्ष पूर्व शिवाजी ने गुरिल्ला युद्धतंत्र का निर्माण किया। नेपोलियन और हिटलर के मास्को अभियान के अनुभवों के सैकड़ों वर्ष पहले, युद्ध के दौरान संभाव्य आपातकाल में आश्रय स्थान के नाते, सुदूर दक्षिण में उपयुक्त प्रदेश सम्पादित करने की दूरदर्शिता उन्होंने दिखायी। शास्त्र के नाते 'जिओपोलिटिक्स' का विकास होने के 250 वर्ष पूर्व उन्होंने सागरीय सत्ता का सूत्रपात प्रयास पूर्वक किया। इतिहास के जिस कालखण्ड में 'सेक्युलर' राज्य की कल्पना पश्चिम में लोकप्रिय नहीं थी, उस समय शिवाजी ने हिन्दू परम्परा के अनुकूल सम्प्रदाय निरपेक्ष धर्मराज्य की स्थापना की।

अपने कर्तृत्व से सम्पादित राज्य के प्रति पूर्ण अनासक्ति, आध्यात्म-प्रवण होने के कारण अर्जित राज्य छोड़कर संत तुकाराम के समक्ष हरि-संकीर्तन में ही शेष जीवन व्यतीत करने की इच्छा प्रकट करना। एक अन्य अवसर पर तो उन्होंने अपना सम्पूर्ण राज्य ही समर्थ गुरू रामदास स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया था। 6 जून, 1674 के दिन सम्पन्न हुआ शिवाजी का राज्यारोहण किसी व्यक्ति का नहीं, धर्म का राज्यारोहण माना गया। हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना, हिन्दू राष्ट्र के सफल प्रत्याक्रमण और हिन्दू संस्कृति के पुनरूत्थान, और विश्व-धर्म की पुनः प्रतिष्ठापना की घोषणा थी।

सनातन काल से हिन्दू राष्ट्र ने जिस आदर्श का संगोपन किया, वही आदर्श मानव रूप धारण कर सिंहासनारूढ़ हो रहा है, यही भावना जनमानस में उस समय थी। स्वयं शिवाजी ने भी समय-समय पर इसी धारणा का उद्घोष किया-

'हिन्दवी स्वराज्य स्थापन होना चाहिए, यह श्री भगवती की इच्छा है। राज्य धर्म का है, शिवबा का नहीं।'

यह तीन सौ साल पूर्व की घटना है। हिन्दुस्थान में चारों ओर पराये आक्रामकों का राज्य, साम्राज्य और धर्म पर आक्रमण, हिन्दुओं में आत्मविश्वास का अभाव, पराये आक्रामकों को हम परास्त कर नहीं सकते, इस तरह का मन का भाव और इन परिस्थितियों में एक बालक मन में निश्चय कि 'मैं पराये आक्रमण का मुकाबला करूंगा उनको पीछे हटाऊंगा, अपने स्वराज्य की स्थापना करूंगा,

धर्मराज्य की स्थापना करूंगा।’ जबकि विरोध में बड़े राज्य और साम्राज्य, बड़ी-बड़ी सेनाएं और सेनापति, राज्य कार्य-धुरंधर लोग और अपार कोष था। उस बालक के पास कुछ नहीं, केवल पांच-पचास अपने समवयस्क लड़कों की लगन। इतनी ही साधन सम्पत्ति थी उसके पास, किन्तु निश्चय के आधार पर इस अवस्था में भी उसने ‘रावण रथी बिरथ रघुबीरा’ की नाई साधन सम्पन्न राज्यों, साम्राज्यों का मुकाबला करते हुए उनको परास्त करके धर्मराज्य की स्थापना की, जिसकी घोषणा ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी पर हुई। उसको कहा गया ‘हिन्दू साम्राज्य दिनोत्सव’। आज की स्थिति में भी इस घटना को, वे ही सिद्धान्त, वे ही आदर्श, वे ही स्वप्न, वे ही लक्ष्य सामने रखकर काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना भी आवश्यक है।

किन्तु ऐसा दिखता है कि दोनों बातों में लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। हमारी हालत यह है कि आदमी जितना अधिक अध्ययन करता है पराये लोगों और पराये सिद्धान्तों के बारे में उसकी उतनी ही अधिक जानकारी बढ़ती जाती है, किन्तु अपने बारे में उसकी जानकारी धीरे-धीरे कम होने लगती है। अपने आदर्श, अपने सिद्धान्त, अपनी व्यवस्था आदि के विषय में जानकारी रखने की इच्छा नहीं रखता और इसके कारण अपनी बात, अपनी कल्पना, अपनी रचना को समझ पाना हमारे भाइयों के लिए बहुत कठिन हो जाता है।

यह वर्तमान शिक्षा पद्धति और प्रचार का परिणाम है। उदाहरण के लिए यदि हमने हिन्दू साम्राज्य का नाम लिया तो लोगों के दिमाग में वह कल्पना नहीं आयेगी जो कल्पना हिन्दू साम्राज्य स्थापित करने वाले छत्रपति शिवाजी के मन में थी। हिन्दू होते हुए भी नये पढ़े-लिखे लोगों का पाश्चिमात्य कल्पनाओं से तो परिचय है किन्तु हिन्दू शब्द में निहित कल्पना से परिचय नहीं है। उनका अध्ययन हिन्दू नहीं, पाश्चिमात्य है। वे ‘हिन्दू साम्राज्य’ शब्द का अर्थ लगाएंगे, उसका अनुवाद करेंगे और कहेंगे साम्राज्य माने राज्य, वह साम्राज्यवाद है। गलत अर्थ, गलत भाषान्तर, गलत समकक्ष शब्द। केवल उधर की एक कल्पना, इधर की एक कल्पना, थोड़ा सा ऊपर से सादृश्य दिखाई दिया तो कहा कि वही बात है, कोई अन्तर नहीं है। वे यह सत्य जानने का प्रयास नहीं करते कि हिन्दुओं की प्राचीन संस्कृति, प्राचीन परम्परा और प्राचीन इतिहास है। आज के अति प्रगत राष्ट्र जिस समय वन्य अवस्था में थे, उस समय सुसभ्य और दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र हमारा ही रहा है। इसलिए इस तरह की अनेक कल्पनाएं, कई रचनाएं हमारे यहां हैं जो पश्चिम में देखने के लिए नहीं मिल सकती। उनका स्वतंत्र अध्ययन न करके कुछ इधर का, कुछ उधर का सादृश्य दिखाते हुए भाषान्तर कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि साम्राज्यवाद खराब है और साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग गलत है। जैसे अब लोग मानने लगे है कि ‘भई! धर्म माने रिलिजन नहीं, रिलिजन माने धर्म नहीं।’ लेकिन अब तक वे कहते थे धर्म यानी रिलिजन है, ‘रिलिजन यानी धर्म है। यह कहने वाले न रिलिजन को जानते है, न धर्म को।’ इस प्राचीन और सनातन राष्ट्र की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहां के हमारे विशेष शब्दों के लिए अंग्रेजी में कोई समकक्ष शब्द नहीं है। उनका अंग्रेजी पर्याय नहीं हो सकता, ठीक-ठीक भाषान्तर भी नहीं हो सकता। उन्हें अपने प्रकृत रूप में ही जाना जा सकता हैं। यह बात न समझते हुए पश्चिम में जो-जो चीजें है, वहीं चीज यहां भी होनी और दिखाई देनी चाहिए यह दुराग्रह रखते हुए यहां की बातों और विचारों पर वही दोषारोपण किया जाता है जो दोषारोपण पश्चिम की कल्पनाओं पर होता है।

> **सनातन काल से हिन्दू राष्ट्र ने जिस आदर्श का संगोपन किया, वही आदर्श मानव रूप धारण कर सिंहासनारूढ़ हो रहा है, यही भावना जनमानस में उस समय थी। स्वयं शिवाजी ने भी समय-समय पर इसी धारणा का उद्घोष किया-**
>
> ‘हिन्दवी स्वराज्य स्थापन होना चाहिए, यह श्री भगवती की इच्छा है। राज्य धर्म का है, शिवबा का नहीं।’

हिन्दू शब्द को यदि समझना है तो इसकी परम्परागत अर्थ-सम्पदा, अर्थच्छाया को समझना होगा। जिसके राज्यारोहण दिवस को हिन्दू साम्राज्य दिनोत्सव के रूप में मनाया जाता है, उस शिवाजी के बारे में क्या हम जानते नहीं कि प्रारम्भ में ही स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि ‘यह व्यक्ति का नहीं, कुल का नहीं, जाति का नहीं, धर्म का राज्य है।’ राज्य स्थापना का प्रयास उन्होंने सत्ता के मोह में नहीं किया। हिन्दू स्वराज्य का निर्माण उन्होंने धर्म के संस्थापक के एक साधन और माध्यम के रूप में किया था। यही कारण है कि हम देखते है कि शिवाजी ने अपने जीवन में तीन बार स्वकष्टार्जित, स्वपराक्रामार्जित सत्ता छोड़ दी थी। अपने गुरू रामदास को उन्होंने गुरूदक्षिणा के रूप में उनकी झोली में अपना स्वकष्टार्जित स्वराज्य समर्पित कर दिया था। जिसके मन में केवल राजनीतिक आकांक्षाएं होती हैं वह ऐसा नहीं कर सकता। जो यह मानता है कि यह मेरा नहीं धर्म का राज्य है, अर्थात् राजसत्ता अपने पास होते हुए भी सत्ता की पिपासा नहीं, सत्ता का मोह नहीं, और जो धर्म स्थापना के एक साधन के रूप में सत्ता सम्पादन की ओर देखता है वही आदमी यह कार्य कर सकता है। किन्तु इस हिन्दू पृष्ठभूमि, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, वायुमण्डल की पृष्ठभूमि को न जानते हुए यदि पश्चिम के तौर-तरीकों के संदर्भ में अर्थ लगाए गए तो हिन्दू बातों को समझना बहुत मुश्किल होगा।

शिवाजी के ही संदर्भ में मैं केवल उदाहरण के लिए बताता हूं कि किस तरह हिन्दू अर्थच्छाया न समझने के कारण गलतफहमियां हो सकती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के नेता कामरेड डांगे का कहना है कि हिन्दुओं के हर एक शब्द का कुछ अर्थच्छाया (कनोटेशन) है। उस अर्थच्छाया को न समझने के कारण गड़बड़ होती है, उसे ठीक ढंग से समझा नहीं जा सकता। इसलिए जिन एक-दो कल्पनाओं के बारे में हमारे तथाकथित प्रगतिवादी, प्रोग्रेसिव लोग ‘प्रोग्रेसिव’ का मतलब, जिसको खुद के बारे में जानकारी नहीं, किन्तु दुनियां के बारे में जानकारी होती है, टीका करते थे। उसका उदाहरण डांगे ने दिया ‘यह ठीक है कि अवतार भगवान का ही होता है।’

कई प्रगतिवादी लोगों ने इसका मखौल उड़ाना शुरू किया कि यह दकियानूसी विचार है कैसा अवतार? अवतार की बात गलत है। डांगे ने कहा, ‘यह कहने वाले जानते ही नहीं कि अवतार शब्द की विशेष परम्परागत अर्थच्छाया क्या है? उन्होंने बताया कि जब समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में विकृतियां और दोष निर्माण होने के कारण समाज का पतन होने लगता है। उस समय जो महापुरूष सामने आकर उन विकृतियों और दोषों को दूर करके नई परिस्थिति के अनुकूल समाज की रचना करता है, उसे अवतार माना जाता है।’ इसका मर्म न समझते हुए, स्वयं को एकमेव प्रगतिवादी और ‘प्रगमनशील’ बताने वाले लोग यदि कहते है कि अवतार वगैरह क्या है, यह सब पोंगापंथी है, तो ऐसे लोगों के अभिप्राय को हमें कोई महत्व नहीं देना चाहिए। उनको न तो परम्परागत शब्दों का अर्थ ज्ञात है, न उनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही है। वे पूर्वाग्रह ग्रस्त लोग हैं। वे अपने अतिरिक्त शेष लोगों को बुद्धू समझते है। जिनके मन में इस तरह की एक सस्ती और एक लड़कपन की भावना है, हिन्दू कल्पनाओं के बारे में उनके विचारों को महत्व देना हम आवश्यक नहीं समझते। ▪

समाज और विचारधारा

जो तथाकथित समाजवादी विचारधाराएं हैं, उनमें सबसे बड़ी खराबी है कि व्यक्ति के स्वरूप का और समाज के स्वरूप का जो सही ज्ञान होना चाहिए, वह उनके पास नहीं।

इनमें भी लोग सब ताकत अपने हाथ में लेकर बाकी के समाज को सुख-सुविधाओं से वंचित रखते हैं।

पं. दीनदयाल उपाध्याय

यह तो स्पष्ट है कि समाजवाद के नाम से जो विषय चल रहा है तथा बहुत ही व्यापक और एक प्रकार से प्रभावी रूप से जिन कम्युनिस्ट देशों में इसका प्रसार होता दिख रहा है, उसमें व्यक्ति का और समाज का भी जैसा भला होना चाहिए, वैसा न होकर दूसरी ओर बुरा हाल है। यह बात अलग है कि देशों ने भौतिक दृष्टि से प्रगति कर ली होगी, लेकिन भौतिक प्रगति को समाजवादी पद्धति से जोड़ नहीं सकते। दुनिया के और भी देश हैं, जैसे अमरीका, उसने भी प्रगति की है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें अमरीका ने रूस से अधिक प्रगति की है। कुछ क्षेत्रों में रूस भी आगे निकल गया है। परंतु इन चीजों से विचारधारा के बारे में कोई निष्कर्ष निकालें तो वह गलत होगा। ये निष्कर्ष प्रचार की दृष्टि से निकाले जाते हैं।

पिछले दिनों एकाएक समाचार आया कि चीनी लोग एवरेस्ट पर चढ़ गए। कैसे चढ़ गए, इसका पता नहीं। वह पहले चढ़ रहे थे, इसकी भी खबर नहीं। फिर समाचार आया कि रात के एक बजे चढ़े। यह भी बताया गया कि उनकी यह विजय कम्युनिस्ट विचारधारा की विजय है। पर जानकार लोगों ने बताया कि इन समाचारों से ही पता लगता है कि ये गलत हैं। संभव भी हो तो विचारधारा के साथ तो इसको नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन लोग जोड़ते हैं। अभी अंतरिक्ष में यात्री को भेजा गया, फिर एक महिला को भेजा गया। उसके बारे में भी इसी प्रकार का विचार करते हैं। हमें वास्तविकता का गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके पीछे तर्क या वैज्ञानिक ढंग के साधन नहीं। ये आधुनिक ढंग की रूढ़ियां हैं। जैसे छींक आ गई और लाभ नहीं हुआ तो धारणा हो जाती है कि छींक आ जाने से ही काम बिगड़ा है। यद्यपि इसमें कोई कारण-कार्य संबंध जोड़ा नहीं जा सकता। अनेक बार ऐसे भी हुआ होगा, जब छींक आने पर भी काम हुआ होगा, परंतु उसको कौन ध्यान में रखता है। एक जगह समुद्र में एक मंदिर था। उसके पुजारी ने मंदिर में उन सज्जनों की सूची बनाकर टांगी हुई थी, जिनका समुद्र यात्रा से मंदिर दर्शनार्थ आने पर कुछ न बिगड़ा हो अर्थात् जो डूबे नहीं तथा सकुशल लौट आए थे। इसका मन पर प्रभाव पड़ता है। एक बार एक दार्शनिक ने पुजारी से पूछा, ''जो समुद्र यात्रा पर गए और डूब गए, उनका नाम नहीं लिखा। क्यों?'' वे नाम तो उसके पास नहीं थे। इस प्रकार कुछ को छिपा लिया जाता है और कुछ को प्रकट किया जाता है और फिर गलत तरीके से उनमें कारण-कर्म भाव ढूंढ़ लिया जाता है। वैसे ही आज भी बहुत सी चीजें होती हैं।

हिटलर पिछली बार रूस के खिलाफ लड़ा और रूस जीत गया। इससे पहले वह जापान से हार गया था। तो एकमेव कारण कि रूस में साम्यवाद के कारण यह विजय हुई, ऐसा बताया जाने लगा। परंतु यदि यही तर्क लगाया जाए तो इंग्लैंड और अमरीका में तो साम्यवाद नहीं था। वे कैसे जीत गए और अमरीका वाले कह सकते हैं कि पिछली लड़ाई में अमरीका के आने के बाद जो हिटलर लड़ा तो वह हारा। तो यह सब हुआ अमरीका के पूंजीवाद के कारण। वह यह कह सकता है, पर इसमें भी कोई बल नहीं।

इन चीजों को हटाकर देखें तो पता लगेगा कि जो तथाकथित समाजवादी विचारधाराएं हैं, उनमें सबसे बड़ी खराबी है कि व्यक्ति के स्वरूप का और समाज के स्वरूप का जो सही ज्ञान होना चाहिए, वह उनके पास नहीं। इनमें भी लोग सब ताकत अपने हाथ में लेकर बाकी के समाज को सुख-सुविधाओं से वंचित रखते हैं।

यह विचारधारा वहीं आकर खड़ी हो गई, जहां से इसने प्रारंभ किया था। व्यक्ति जितना गुलाम पूंजीवादी यूरोप में था, संभवतः उससे अधिक गुलाम समाजवादी व्यवस्था में आज है। जितनी विषमताएं पूंजीवादी यूरोप में थीं, उससे अधिक विषमताएं समाजवादी यूरोप में हैं। विषमताओं का मापदंड बदल लिया गया है, लेकिन उससे अधिक विषमताएं लाई गई हैं। विषमताओं का रूप बदल गया है। जैसे किसी को रुपया मासिक मिले और किसी को दस हजार रुपए तो यह कितनी बड़ी विषमता है। यह विषमता कम होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई दस हजार रुपए को यह रूप दे कि वेतन मिलेगा दो हजार शेष की बाकी चीजें मुफ्त, जैसे मकान, यातायात व्यय आदि। ये सब सरकार उसे मुफ्त देगी। नतीजा यही होगा

समाज की एक सत्ता मानने के बाद समाज की शक्ति का अंकन इस प्रकार नहीं होगा। वह भिन्न वस्तु है। हम उसके एक अंग हैं, परंतु वैसे ही हैं जैसे शरीर का हाथ से संबंध होता है।

हम उसके एक अवयव हैं, परंतु हमारी एक स्वतंत्र सत्ता भी है। एक प्रकार के लोग तो यह मानते हैं कि समाज एक सत्ता है और मनुष्य एक पुर्जा मात्र है।

कि विषमता शायद और बढ़ जाएगी। जब अंग्रेज यहां थे तो उनके वायसराय के एक्जीक्यूटिव के जो मेंबर थे, उनको साढ़े तीन या चार हजार तनख्वाह मिलती थी। इनकम टैक्स देने के बाद बाईस सौ-तेईस सौ रुपया बचता था। नई सरकार ने तनख्वाह को कम कर दिया। तनख्वाह दो हजार सात सौ पचास रुपए कर दी, लेकिन इनकम टैक्स माफ कर दिया। यदि आप देखेंगे कि खुश्चेव पर कितना खर्च होता है तो अनुमान लगेगा कि उसकी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है। रूस में आज भी आय का अनुपात कुछ के कहने के अनुसार एक और दौ सौ है। एक और अस्सी तो स्वीकार किया ही जाएगा।

वे शोषण समाप्त करने की बात कहते हैं। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में शोषण समाप्त हुआ मान लिया जाए तो भी राजनीतिक दृष्टि से शोषण प्रारंभ कर दिया है कि मार्क्स ने जो अपने सारे निष्कर्ष निकाले थे तो उसमें 'सरप्लस वैल्यू' का सिद्धांत रखा था। उस अर्थव्यवस्था का आधार था जहां मंडी में मूल्य मांग और पूर्ति के संतुलन में तय होता है। फिर वास्तविक मूल्य क्या है, विनियम मूल्य क्या है। वह कितनी मात्रा में सही है। इन सबके पचड़े में मैं नहीं पड़ता। लेकिन कम्युनिस्ट देशों में 'मार्केट इकोनॉमी' नाम की चीज है ही नहीं। यह 'सरप्लस वैल्यू' मजदूर के पास जाती है, यह सच नहीं। यह आज राज्य के पास पहुंच जाती है और फिर कुछ व्यक्तियों के पास जाती है। आरंभ में शक्ति सुविधाएं कुछ हाथों में केंद्रित थीं। झगड़ा यहीं से प्रारंभ हुआ था कि शक्ति सुविधा कुछ हाथों में नहीं रहनी चाहिए, परंतु शक्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित रही और बाकी के लोगों में अंतर नहीं आया, बल्कि जिन देशों में कम्युनिस्ट पद्धति नहीं, वहां अवश्य कुछ अंतर आया है।

गलती यह है कि व्यक्ति और समाज का वास्तविक संबंध क्या है, स्वरूप क्या है, इसको लोग समझ नहीं पाए। समाज लोगों को मिलाकर बना है, यह गलत है। व्यक्तियों का समूह समाज नहीं, समाज की अपनी एक सत्ता है, जीवमान सत्ता है उतनी ही, जितनी एक प्राणी की होती है। प्राणी उसका अंग जरूर है लेकिन यह एक निर्जीव अंग जैसा नहीं, जैसे कि मोटर के पुर्जे होते हैं। यह वैसा ही है जैसा एक पूरा पेड़ होता है और उस पेड़ का एक पत्ता।

पत्तों को मिलाकर पेड़ नहीं बनता। कोई यह कहेगा क्या कि हाथ, पैर, नाक, कान मिलाकर व्यक्ति बन जाता है? पुर्जों को मिलाकर मोटर बनेगी, पर मनुष्य शरीर के लिए ऐसा नहीं। 19वीं सदी में यही लोग बोलते थे कि जैसी मशीन है, शरीर भी वैसा ही है, जरा जटिल है। परंतु मशीन तो पुर्जे मिलाने से तैयार हो जाती है, शरीर नहीं हो पाता। क्योंकि उसमें प्राण फूंकना जरा टेढ़ा काम है। अभी तक किसी विज्ञानवेत्ता ने इसमें सफलता नहीं पाई।

पंचतंत्र में एक कहानी है कि कुछ पढ़ने वालों में एक को प्राण फूंकने की विद्या आती थी। उसने रास्ते में हड्डियों को देखा तो जोड़-जोड़कर उसका ढांचा खड़ा कर दिया। वह व्याघ्र था। जब प्राण फूंकने लगा तो उसका दूसरा साथी जो व्यावहारिक था, उसे मना करने लगा कि यह जीवित हो जाएगा तो तुझे खा जाएगा। उसके न मानने पर साथी तो पेड़ पर चढ़ गया और इधर जैसे ही व्याघ्र में जान आई। उसने सबसे पहले इसी का शिकार किया। यह कहानी केवल इसलिए है कि विद्या के साथ व्यावहारिकता भी चाहिए। व्यावहारिकता ने उसकी जान बचा दी। लेकिन यह तो एक कहानी है। वस्तुतः कोई प्राण फूंक नहीं सकता।

यह तो सत्य है कि शरीर में एक प्राण है। वास्तव में तभी इसके अंग-प्रत्यंग शरीर के सुख-दुःख को अनुभव करते हैं और इसी नाते सब काम करते हैं। समाज भी एक प्राणवान चीज है। समाज में भी वह गुण है, जो व्यक्ति के अंदर है। मनोवैज्ञानिक तो इसको स्वीकार भी करने लगे हैं कि समाज का मस्तिष्क होता है, जिसे group mind नाम दिया गया है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से जो खून देखकर भी घबराएगा, वह भी राष्ट्र के लिए लड़ता है और फौरन उत्साह से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे व्यक्ति में भाव होते हैं, कर्म होते हैं, वैसे ही समाज की भावनाएं होती हैं, कर्म होते हैं। यह समाज के सभी व्यक्तियों के भावों या कर्मों का कुल जोड़ नहीं होता। इसके लिए गणित के अनुसार कैलकुलेशन का विचार नहीं किया जा सकता। यदि सबकी ताकत को जोड़ दिया जाए, जैसे राष्ट्रीय आय के लिए करते हैं कि प्रत्येक की आय का योग औसत निकाल लिया, वैसे समाज की शक्ति के लिए नहीं होगा।

समाज की एक सत्ता मानने के बाद समाज की शक्ति का अंकन इस प्रकार नहीं होगा। वह भिन्न वस्तु है। हम उसके एक अंग हैं, परंतु वैसे ही हैं जैसे शरीर का हाथ से संबंध होता है। हम उसके एक अवयव हैं, परंतु हमारी एक स्वतंत्र सत्ता भी है। एक प्रकार के लोग तो यह मानते हैं कि समाज एक सत्ता है और मनुष्य एक पुर्जा मात्र है। दूसरे मानते हैं कि व्यक्ति सत्ता है, समाज समूह मात्र है। दोनों गलत हैं। व्यक्ति की अपनी सत्ता है, समाज की भी उतनी ही प्राणवान सत्ता है। दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं। हाथ शरीर से संबंधित है, परंतु हाथ की अपनी विशेषता है। प्रत्येक जीवाणु की अपनी सत्ता है। वह शरीर की सत्ता से मिलकर काम करते हैं। ▪

- प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल जी ने होली पर कार्यकर्ताओं तथा नागरिकों से आत्मीय भेंट कर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

- प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल जी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएँ दीं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
1.25 करोड़

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 34 वीं किस्त की राशि हितग्राही बहनों के खातों में अंतरित की।

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने दुर्लभ प्रजाति के कछुए एवं घड़ियालों को पानी में छोड़ा।

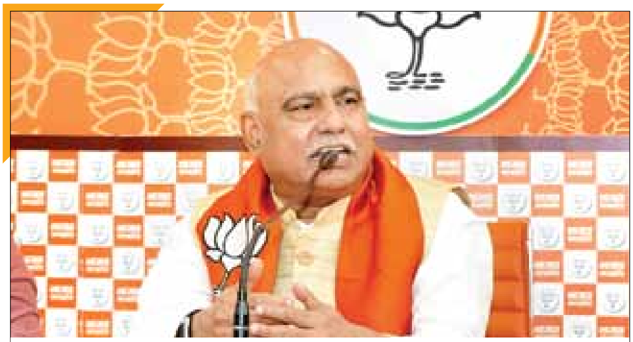

- प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा की परिचयात्मक बैठक को संबोधित किया।

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल ने महिला मोर्चा द्वारा आयोजित ‘बहनों की पाती भैया के नाम अभिव्यक्ति’ कार्यक्रम में सहभागिता की।

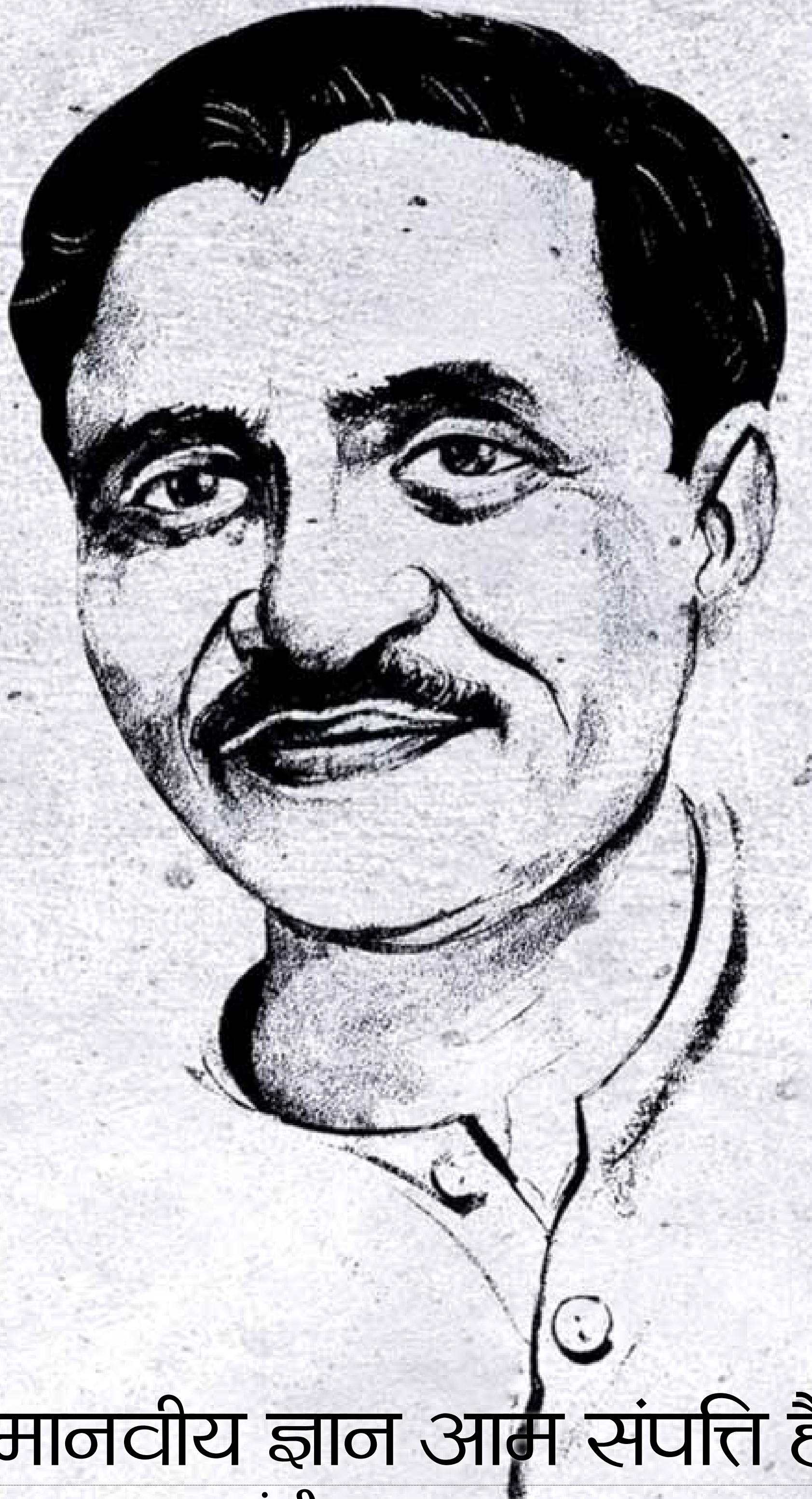

मानवीय ज्ञान आम संपत्ति है

पं. दीनदयाल उपाध्याय